साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

R.N.I. No.: MP/HIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Webite: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9425125569
+91 9479535569

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 17 अंक 52 प्रति सोमवार इंदौर, 29 जुलाई से 04 अगस्त 2024 पृष्ठ 8 मूल्य 5/- रुपए

पुतिन की फिर परमाणु हथियार बनाने की धमकी

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को धमकी दी कि यदि अमेरिका जर्मनी या यूरोप में कहीं और मिसाइल तैनात करने का इरादा जताता है तो वह मध्यम दूरी के परमाणु हथियारों का उत्पादन पुनः शुरू कर देंगे।

पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में एक नौसैनिक परेड के दौरान कहा, 'यदि संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसी योजनाओं को क्रियान्वित करता है, तो हम अपने आप को मध्यम और छोटी दूरी की हमला क्षमताओं की तैनाती पर पहले अपनाए गए एकतरफा प्रतिबंध से मुक्त मानेंगे।'

पुतिन ने कहा कि अब रूस में 'ऐसी अनेक प्रणालियों का विकास अंतिम चरण में है।'

रूसी राष्ट्रपति ने चेतावनी देते हुए कहा, 'हम अमेरिका, यूरोप और दुनिया के अन्य क्षेत्रों में उसके उपग्रहों की कार्रवाइयों को ध्यान में रखते हुए उनकी तैनाती में समान कदम उठाएंगे।'

ऐसी मिसाइलें, जो 500 से 5,500 किलोमीटर (300-3,400 मील) तक की दूरी तक यात्रा कर सकती हैं, 1987 में अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा हस्ताक्षरित हथियार नियंत्रण संधि का विषय थीं।

लेकिन वाशिंगटन और मॉस्को दोनों ने 2019 में मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से खुद को अलग कर लिया और एक दूसरे पर उल्लंघन का आरोप लगाया।

रूस ने बाद में कहा कि वह ऐसी मिसाइलों का उत्पादन तब तक पुनः शुरू नहीं करेगा जब तक कि अमेरिका विदेशों में मिसाइलें तैनात नहीं करता। जुलाई की शुरुआत में, वाशिंगटन और बर्लिन ने घोषणा की कि जर्मनी में टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों सहित लंबी दूरी की अमेरिकी मिसाइलों की 'प्रासंगिक तैनाती' 2026 में शुरू होगी। पुतिन ने कहा कि 'महत्वपूर्ण रूसी प्रशासनिक और सैन्य स्थल' ऐसी मिसाइलों की रेंज में आएंगे, जो 'भविष्य में परमाणु हथियारों से लैस हो सकते हैं, जिससे हमला होने के 10 मिनट के भीतर हमारे क्षेत्र उनकी जद में आ जाएंगे।'

रूसी राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि अमेरिका ने हाल के अभ्यासों में डेनमार्क और फिलीपींस में टाइफॉन मध्यम दूरी की मिसाइल प्रणाली तैनात की है।

(शेष पेज 3 पर)

क्या पीथमपुर का रेमकी का भस्मक इस योग्य है?

मिक की समाप्ति से पूर्व भस्मक की कराई जाए अंतरराष्ट्रीय एजेंसी से जांच

भोपाल की यूनियन कार्बाइड का मिथाइल आइसोसायनाइड का 26 टन कचरा जिसे पीथमपुर की रेमकी कंपनी में जलाया जाएगा वह कंपनी दक्षिण भारत की पूर्व से अपने भ्रष्टाचारों जलसाजिओं के लिये पूरे देश में कुख्यात है।

मैं पिछले 18 सालों से लगातार कह रहा हूं जिस रेमकी ने अपना इंसीनेरेटर प्लांट कचरे के निष्पादन के लिए डाला है।

उसके सच के बारे में मैं 18 साल से लगातार लड़ रहा हूं। सन 2006 में इस इंसीनेरेटर प्लांट के लिए 60 एकड़ भूमि की आवश्यकता थी। जो एकेवीएन इंदौर द्वारा मात्र 20 एकड़ दी गई। प्लांट की 60 एकड़ भूमि पर लागत 25 करोड़ थी। जिसमें 8 करोड़ 66 लाख की सब्सिडी थी। जब मात्र भूमि ही 20 एकड़ मिली तो इस भस्मक परियोजना की लागत भी 8.50 करोड़ ही रह गई। इसमें उस समय डेढ़ करोड़ रुपए की रिश्वत बांटी गई। ताकि कंपनी वह 5 करोड़ में ही प्लांट निर्माण करके 25 करोड रुपए वसूल सके और उसने वसूले। उस बंदर बांट में

जब 40 साल में मिथाईल आइसो साइनाइड से कोई नुकसान नहीं, तो वहीं रहने दिया जाये। या 300 करोड़ हजम करने का खेल

सभी शामिल थे। तब से यह कंपनी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गुजरात और राजस्थान के खतरनाक रसायनों के घातक कचरे को निष्पादित करने का कार्य कर रही है। यथार्थ में यह सब फर्जी है। निर्धारित कीमत 6.50 रुपए प्रति किलो की अपेक्षा रु. 25 किलो तक वसूली जा रही है। दूसरी तरफ वह सारा कचरा कंपनी को जलाकर राख को भी भूमिगत तलघर में दबा कर रखना था। जब इस कंपनी की प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखी गई तो इस समय मैंने उसकी जनसुनवाई में कहा था। कि आखिर पीथमपुर की जिस पहाड़ी पर ही यह भस्मक बनाया जा रहा है। बरसात में वहां से पानी बहकर नर्मदा में जाएगा। दूसरी तरफ रास्ते के सारे भूमिगत व भूमि पर बहने वाले जल स्रोतों को रासायनिक घातक बना फसलों व मानव स्वास्थ्य को भी दूषित करेगा। पीथमपुर के कुछ युवाओं की इस भस्मक की शिकायत मिलने के साथ उसके आसपास के स्त्रोतों को रासयनिक घातकता से खेतों, बोरिंगों को खराब कर चुका है।

(शेष पेज 2 पर)

केंद्रीय बजट 2024 झूठे समन्कों की बाजीगरी, मीडिया पर खर्च कहीं नहीं

मध्यमवर्गीय को निचोड़ जालसाज पूंजीपतियों को बढ़ाना

बचतों को हतोत्साहित करने से, चंहुदिशी बर्बादी, उद्योग व्यवसाय रोजगार बढ़ाने कहां से आएगा धन

भारत सरकार में बैठे पूंजीपति व बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रखेले जाहिल वाचाल मोदी व उसकी गिरोह की वित्त मंत्री सीतारमण का सातवां बजट भी वही पूंजी पतियों को पालने और 30 करोड़ मध्यमवर्गीय 80 करोड़ गरीबों को निचोड़ने का षड्यंत्रकारी खेल सिध्द हुआ। जबकि आयकर की 3 लाख की सीमाओं पर 15 वर्ष से घूमता कुछ घटा बढ़ाकर सीमा को बढ़ाया नहीं गया। जबकि यही धूर्त शासकीय योजनाओं में नौकरियों में, शिक्षा, छात्रवृत्ति में 8 लाख रू से कम आय को गरीबी रेखा में मान आदिवासी अनुसूचित जाति जनजाति में आरक्षण में सुविधाओं का लाभ पानेवाले को पात्र मानते हैं। तो केंद्र सरकार का यह स्वयं के द्वारा निर्धारित दोहरा रवैया आम सवर्ण के साथ क्यों अपनाया जाता है? जबकि 80% उच्च जाति वर्ग में गिने जाने वाले लोगों को शासकीय सुविधाओं का लाभ 8 लाख से काम आय होने पर भी नहीं मिलता। वे शासकीय नौकरी नौकरी में रहते हुए पदोन्नति आदि में पात्र नहीं समझ जाते। तो कम से कम आम मध्यम वर्गीय को 8 लाख तक की सीमापर आयकर मुक्त होना चाहिए थाजैसा कि मैंने लिखा था सीमा को यथार्थ में 15 साल के बाद में तो 10 लाख तक लाना चाहिए ताकि बच्चों को प्रोत्साहन मिले और वही रचते हैं जो बैंकों में जाएगीबाद मेंव्यवसाय उद्योग धंधों को बढ़ाने रोजगार देने में काम आएंगे परंतु महाधूर्त पूंजीपतियों के रखले प्रधानमंत्री मोदी ने उस सीमा को नहीं बढ़ाया। उल्टे ही मध्यमवर्गीम को कमजोर करने का षड़यंत्र किया।

डाका डालना इसी को कहते हैं...

मोदी सरकार ने बहुत प्यार से 'इंडियन मिडिल क्लास' को बेवकूफ बनाया है। 23 जुलाई 24 को पेश हुए बजट में संपत्ति की बिक्री पर मिलने वाले इंडेक्सेशन बेनिफिट को खत्म करने की घोषणा की गई है। अब आप अपनी प्रॉपर्टी की खरीद कीमत नहीं बढ़ा पाएंगे और प्रॉपर्टी को बेचने से होने वाले पूंजीगत लाभ को कम नहीं कर पाएंगे।

अब तक की व्यवस्था में प्रॉपर्टी की सेल से होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) पर इंडेक्सेशन बेनिफिट के भीतर 20% टैक्स लगाया जाता था। अब प्रॉपर्टी की सेल पर पूंजीगत लाभ के लिए इंडेक्सेशन बेनिफिट के बिना 12.5% का नया LTCG टैक्स रेट लागू होगा। मान लीजिए आपने वित्त वर्ष 2010 में 25 लाख रुपये में एक फ्लैट खरीदा था। अब अगर 2024 में आप उसे करोड़ रुपये में बेच देते हैं तो अब तक के नियमों के अनुसार 25 लाख रुपये की खरीद कीमत को इनकम टैक्स द्वारा नोटिफाई किए गए CII नंबरों के साथ बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस बजट में नया नियम प्रस्तावित है। जिसके मुताबिक अब आप ण्घ्घ् के अनुसार खरीद मूल्य को बढ़ा नहीं पाएंगे और बिक्री मूल्य से खरीद मूल्य को कम करके पूंजीगत लाभ की गणना करनी होगी।

सीआईआई क्या है

इनकम टैक्स विभाग हर साल इंडेक्सेशन बेनिफिट की गणना में उपयोग किए जाने के लिए एक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स (CII) घोषित करता है। इस इंडेक्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की इन्फ्लेशन-एडजस्टेड कॉस्ट की गणना करने में प्रयोग किया जाता है और टैक्सेबल कैपिटल गेन का निर्धारण करने के लिए एसेट की सेल वैल्यू से इन्फ्लेशन-एडजस्टेड एक्विजिशन कॉस्ट को कम कर दिया जाता है।

उदाहरण के लिए आपने 2010 में एक प्रॉपर्टी एक लाख रुपये में खरीदी। तब सीआईआई 100 था। अब आपने 2024 में उस प्रॉपर्टी को 1.6 लाख रुपये में बेच दिया और इस साल सीआईआई नंबर 140 है।

(शेष पेज 6 पर)

साप्ताहिक समय माया

संपादकीय

गरीब और गरीब, अमीरों को और अमीर

प्रजा को आर्थिक रूप से कुचलने व विकास कमजोर होगा !

आम बजट के पूरे अध्ययन के बाद जानकार मर्मज्ञ,आर्थिक समीक्षक और आर्थिक मीमांसक कहते हैं कि यह बजट सिर्फ़ लिपापोती का लॉलीपॉप हैं और शाब्दिक मकड़जाल से पूरे राष्ट्र को मूर्ख व मुग़ालते में रखने का आर्थिक धोखा मात्र हैं, जो हर वर्ग की छाती पर नये नये व संगीन संकट खड़ा करेगा और आर्थिक बर्बादी से भरी विषमताओं का दौर पहले से अधिक विकराल होगा, क्योंकि ऊँठ के मुँह में ज़ीरा नहीं बल्कि झूठ के फूव्वहारे से फुस्स होने वाली हवा भर की राहत तो दी हैं वहीं हिमालयी की ऊँचाई से अधिक नए टैक्सों के रूप में केन्द्र द्वारा पाँच लाख करोड़ और राज्य दोनों को मिलाले तो पिछले वर्ष के मुक़ाबले छ लाख करोड़ के नये टैक्स देने को प्रजा को मजबूर होना पड़ेगा.इस बार के बजट की यही प्रमुख सजा प्रजा को ओर अधिक भुगतनी पड़ेगी. इसमें महँगाई कम करने के कोई भी किंचित् मात्र उपाय या कदम नहीं उठाने के चलते अगर बजट के बाद हर वर्ष की तरह ओर कोई नया टैक्स लगाने की आदि मोदी सरकार कोई नया टैक्स न लगावे तो भी हर आम आदमी को बढ़ती महंगाई के चलते छोटों व निम्न मध्य वर्ग को जी एस टी और पूरे मध्यम वर्ग, कारोबारियों,व्यापारियों व व्यवसाईयों को जी एस टी के साथ प्रत्यक्ष कैरों व नौकरी पेशा वालों को ई एम आई पर पिछले साल ही बढ़ी ब्याज दरों के चलते प्रति व्यक्ति पर साठ हज़ार का वर्ष का अतिरिक्त भार उठाना होगा और वर्तमान की तरह मुद्रा स्फीति व महँगाई बढ़ती रही तो हर व्यक्ति पर हर वर्ष पच्चतर हज़ार का अतिरिक्त टैक्स बढ़ेगा. प्रत्यक्ष टैक्स देने वाले को मात्र 17 हज़ार 500 की छूट देकर उन पर जी एस टी,प्रत्यक्ष आयकर, ई एम आई के ब्याज दरों में बढ़ोतरी के साथ शोर्ट टर्म व लौंग टर्म के शेयर के निवेश पर पैसा निकालने पर कमरतोड़ टैक्स के बढ़ने से हर व्यक्ति पर कम से कम इसी मद पर पच्चीस हज़ार से ज़्यादा अधिक देने को मजबूर बनाकर पुचकारने वाले हाथ से ही थपेड़े मार मार कर दिन में तारे दिखाऐं जाएँगे.

प्रजा को आर्थिक रूप से तबाह व विकास में ओर अधिक स्खलन लाएगा

देश में सरकारी आँकड़ों के अनुसार ग्यारह करोड़ पंजीकृत और ग़ैर पंजीकृत का आँकड़ा जोड़े तो पन्द्रह करोड़ पढ़े लिखे सिर्फ़ संगठित क्षैत्र में बेरोज़गार हैं और असंगठित क्षैत्र को जोड़े तो कुल मिलाकर बाईस से पच्चीस करोड़ बेरोज़गारों में से मात्र एक करोड़ बेरोज़गारों को रोज़गार नहीं सिर्फ़ एक वर्ष सहारा और मात्र बीस लाख को विशेष सहायता दी जानी हैं और हर वर्ष जितनों को सहारा मिलेगा उससे कई गुणा हर वर्ष जुड़ते जाएँगे तो बेरोज़गारी का समाधान तो होगा नहीं. बढ़ती बेरोज़गारी से निपटने, भयावह महँगाई, भीषण भ्रष्टाचार, असाधारण आर्थिक विषमता, कुपोषण व भुखमरी मिटाना मोदी सरकार के एजेण्डे में हे ही नहीं, इसीलिए बजट में इन पर कोई भी कार्य योजना तो छोड़ो उसके लिए कोई ठोस प्रस्ताव भी नहीं सुजाए हैं. कोई बजट यदि क्रय शक्ति, माँग शक्ति, बचत शक्ति को बढ़ाये बिना मुद्रास्फीति, महँगाई, आर्थिक भेदभाव,आर्थिक लूट, आर्थिक विषमता को मिटाए बिना या उस हेतु कोई रोड मैप बनाये बिना आनन फ़ानन में नये नये सरकारी टैक्स, सेंस व अधिभार को थोपने की बेईमान मंशा रखते बजट पेश करे तो वो बजट नहीं सिर्फ़ ठगाई का मकड़ जाल भर हैं. जो सरकार निर्यात को बढ़ाकर राष्ट्रीय आय में इजाफ़ा करने में पूरी तरह से असफल हैं, आयात को कम न कर सकने के चलते प्रतिवर्ष हो रहे अरबों डालर का भीषण राष्ट्रीय नुक़सान व भयावह व्यापारिक व आर्थिक घाटे को कम न कर सके और जो सरकार मैनुफ़ेक्चरिंग सेक्टर को उठाकर और मरणासन्न हो चुके छोटे, अतीव मझौले,मध्यम व्यापार, कारोबार व उद्यम में प्राण न फूंक सके तो फिर कभी बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, महँगाई, आर्थिक विषमता व आर्थिक ग़ैरबराबरी मिटाकर राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी, मुद्रा स्खलन में कमी, श्रम, पूँजी व संसाधनों के सामंजस्य के बिना कोई सार्थक परिणाम कभी नहीं मिल सकता और आर्थिक साम्य व सन्तुलन बराबर नीचे गिरते विकास व समृद्धि को लीलते ही जाता हैं. सरकार नये नये टैक्स लादते जनता की छाती पर बुलडोज़र लादकर इसके साथ जो पेट्रोल डीज़ल आज के अंतर्राष्ट्रीय भाव के अनुसार सारी छीजत, लागत, तमाम तरह के खर्चे व लाभ जोड़ने के बाद साठ रुपये लीटर बहुत ही आसानी से मिल सकता हैं वो बड़ी बदनसीब से हमें केन्द्र व राज्य सरकारों की लूट के चलते नब्बे व सौ रुपये प्रति लीटर देना ही हमारी आर्थिक मौत के अलावा कुछ भी नहीं हैं. यह मोदी सरकार देश की प्रजा को इसी नृशंसता से कुचल रही हैं. पिछले दस वर्षों के सारे बजट एक मात्र पूँजीपतियों की समृद्धि व उनकी लूट को समर्पित थे और इस बार के बजट में पचास से साँठ प्रतिशत पैसा इन्ही लुटेरे कॉरपोरेट कुबेरों के माध्यम व हाथों से इन्फ़ास्ट्रेक्चर डेवलपमेंट के नाम पर व अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं पर खर्च होना हैं याने पहले सीधे हाथ से लूट होती थी अब हाथ घुमाकर होगी.

हास्यास्पद तो यह हैं कि बजट को अच्छा प्रचारित करने के नाम पर सरकार से लाभ उठाने या चापलूसी करने के लिए चैनल, अखबार, व्यापारिक व कारोबारी समूह इतने नीचे गिर आएँ हैं कि समीक्षा व अंकेक्षण की बजाए वित्तमन्त्री के शगूफ़ो व झूमलों वाले शब्दों को कॉपीपेस्ट कर इस खराब बजट को भी महान व अच्छा बजट बताने के लिए मोदी सरकार व भाजपा की निगाह में एक दूसरे से अच्छा होने की भयावह गलाकाट प्रतियोगिता पर सिमट आएँ हैं.

बजट भाजपा के आत्मघात या भाजपा का सूपड़ासाफ़ बजट

इस बार का बजट भाजपा के आत्मघात या भाजपा का सूपड़ासाफ़ बजट बनेगा क्या.. इस बार का बजट मोदी सरकार का भाजपा के लिए आत्मघाती व भयावह संकट का निश्चित कारक बनेगा. यह बात सिहासी हलकों में हर कोई के मुँह से निकल रही हैं, यह सही हैं कि कुर्सी व सरकार दोनों बचाने के जुगाड़ में मोदीजी अपना हाथ बचाकर भाजपा का आँचल जला बैठे हैं. दो राज्यों को अतिरिक्त लाभ देकर करोड़ों की सहायता व राहत के बाद अब देश के दूसरे सभी राज्यों से उन्हें भी ऐसा ही अतिरिक्त फण्ड देने की माँग करते कह रहें कि ऐसा नहीं हुआ तो वे केंद्र के इस अन्याय के खिलाफ़ ज़मीन से लेकर संसद तक लड़ेंगे. भाजपा दो राज्यों को राज़ी करने के चलते बाक़ी सारे राज्यों के वास्ते दुश्मन बन चूकी हैं और यह बात भी सत्य हैं कि केन्द्र सरकार के पास किसी ओर राज्य को अतिरिक्त देने वास्ते उसके खज़ाने में अब कुछ भी नहीं हैं, इसी के परिणाम स्वरूप आगामी छह माह के अन्तराल में भाजपा बिहार को छोड़कर महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखण्ड, दिल्ली आदि की विधान सभा में शर्तिया हारेगी. मगर भलेही भाजपा के पैर सारे राज्यों से उखड़ जाए और बुरी तरह से हार भी जाए मगर मोदीजी की सत्ता हर हाल में बरकरार रहेगी. इस कदम से मोदीजी का तीर बहुत सटीक व सुरक्षित निशाने पर लगा हैं क्योंकि पहला समर्थन दे रहे सारे दल आखिरी साँस तक साथ देंगें और संघ या पार्टी के अन्दर से कभी मोदीजी को बदलने की माँग होगी तो ये बाहरी समर्थन देने वाले सभी यह कहकर मोदीजी की कुर्सी बचा देंगे कि हम सिर्फ़ मोदीजी के साथ हैं और भाजपा किसी ओर को प्रधान मंत्री बनाना चाहती हैं तो वे उस सरकार को समर्थन नहीं देंगे और कारपोरेट घराने भी मोदी के पक्ष में खड़े हों उन्हें बचाएँगे याने कूल मिलाकर कोई अप्रत्याशित हालात नहीं हुए तो मोदीजी पूरे पाँच साल सत्ता पर काबिज रहेंगे मगर इसका यह घातक प्रभाव होगा कि भाजपा न केवल सभी राज्यों में हारेगी बल्कि अगले लोकसभा में भी उसका सूपड़ा साफ़ हो जाएगा. खेल अब यह होगा कि संघ व भाजपा अपना भविष्य बचाने मोदीजी को हटाने और पूरा एन डी ए व समूची कॉरपोरेट लॉबी मोदीजी को बचाने के शीतयुद्ध में जमकर उलझेंगे या फिर खेल ओर किसी तीसरी दिशा में मूड जाएगा.

क्या पीथमपुर का रेमकी का भस्मक इस योग्य है?

पेज 1 का शेष

कंपनी कोई कचरा नहीं जला रही है सब कोई इकट्ठा करके संग्रहित कर रही है। कंपनी का वहां कोई जिम्मेदार बड़ा अधिकारी नहीं है सब कर्मचारी ही खेल कर रहे हैं। इसकी सट्टा का पता लगाने के लिए मैंने पीथमपुर के खेतड़ी कार्यालय मध्य प्रदेश प्रदूषण फैलाओ और वसूली करो मंडल को सूचना के अधिकार में पत्र दिया था। और रेमकघ कंपनी के बिजली के बिल मांगे थे। यदि विद्युतकीय भस्मक का प्रयोग किया जा रहा होता तो हजारो टन प्रतिमाह लाखों में बिल आना चाहिये था। सूत्रों के अनुसार वहां बैठा क्षेत्रीय अधिकारी मंडराई शराब के नशे में धुत रह केवल मोटी वसूली में व्यस्त रहता है। वह वसूली स्वंय नहीं करता वह कार्य अस्थाई कंप्यूटर ऑपरेटर कर्मी से करवाता है। यूनियन कार्बाइड के मिथाइल आइसोसायनाइड को बेशक 40 साल हो गए। प्रदूषण मंडल के हरामखोर अधिकारी जहां वर्तमान में सदस्य सचिव घोर भ्रष्ट जालसाज डकैत अच्युत आनंद मिश्रा पुनः करोड रुपए खर्च कर सदस्य सचिव बन गया और पूरे मध्य प्रदेश से के प्रदूषण कारी उद्योगों खदानों कॉलोनीयों वर्क शॉप फैक्ट्रियों से मोटी वसूली कर रहा है। इसी जालसाज ने 2011-12 में सदस्य सचिव बनते ही प्रदेश की सारी फैक्ट्रियों उद्योगों से दरवाजे पर लगाए जाने वाले जल व वायु (प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम के अंतर्गत लगाई जाने वाले उद्योग के नाम और विवरण पट्टिकाओं को जिसमें वहां क्या काम होता है। कौन सी घातक पदार्थ का उपयोग किया जाता है उससे किस प्रकार का प्रदूषण निकलता व फैलाता है। आपातकाल की स्थिति में आसपास की राह वीडियो और जनता को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वह सारे बोल पूरे मध्य प्रदेश की सभी फैक्ट्रियों से निकलवा कर बाहर करवा दिए। अब किसी भी उद्योग या फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर ऐसे विवरण पट्टिकाएं लगी नहीं मिलती ना फैक्ट्री का उद्योगों का नाम और काम किसी भी बाहरी व्यक्ति या आगंतुक को समझ नहीं आता और यह इसी भ्रष्ट मक्कार की जालसाजी का परिणाम है जो कचरे को जलवाकर उसमें लगभग 300 करोड़ का लेनदेन करना चाहता है। स्वाभाविक है उसे कचरे को भोपाल की फैक्ट्री से निकालना और पूरे रास्ते में ढंकने व चारों तरफ से बंद करने के बाद में भी वह घातक अवशिष्ट घातक ही रहेगा। 4 दिसंबर 1984 को उसकी गैस से लगभग 20000 लोगों की मृत्यु होने के साथ लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। तो इसका ठोस अवशिष्ट पूर्णतः समाप्त होकर साधारण मिट्टी कैसे बन सकता है? आखिर लाखों साल पुराने नमक की खदानों से नमक खारे पन के साथ, धातुओं सोना चांदी तांबा लोहा, तत्वों जैसे गंधक के अयस्क धरती की खदानों से कैसे निकलते हैं? जबकि सब लाखों साल से मिट्टी में दबे हुए हैं। तो सबको मिट्टी हो जाना चाहिए था।

और अगरयूनियन कार्बाइड का संग्रहित मिथाइल आइसो सायनाइड मिट्टी हो गया है। तो क्या जरूरत है। भोपाल से उठाकर इंदौर के पास पीथमपुर लाकर जलाने की। जैसे भोपाल में पड़ा हुआ है पड़ा रहने दीजिए जब 40 साल में प्रभावहीन मिट्टी हो चुका और अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा हैतो फिर यहां लाने की क्या जरूरत है?

पीथमपुर धार में बैठा हुआ मंडराई जिसके हाथ में लगभग 3000 बड़े उद्योग पीथमपुर लेबड़, झाबुआ मेघनगर, खरगोन हैं। और जिनसे लगभग 10 करोड रुपए प्रति माह की वसूली की जा रही है। मेघनगर में अधिकांश रसायन फैक्ट्रियां हैं और उन सब का विषैला रसायन युक्त पानी एक बड़े तालाब में जाता है अधिकांश फैक्ट्रियां वहां गुजरात से लगे होने के कारण गुजरातियों की है। जो मोदी के दम पर सभी प्रकार के कानूनों का उल्लंघन कर पैसा फेंक कर अपना उत्पादन सतत जारी रखे हुए हैं। और वह उसे रासायनिक जल को बिना उपचारित किए हुए तालाब में बहा रहे हैं। जिससे लगभग 100 से ज्यादा गांव जुड़े हुए हैं। और वहां के वह सबसे ज्यादा गांव की ग्रामीणों का पेयजल स्रोत होने के साथ-साथ उसका पानी पशुओं गाय भैंस के साथ में बकरियां आदि भी पीती हैं और कई बार10-10 बीस बकरियां मर चुकी हैं। परंतु इस धूर्त मंडराई के कारण उन फैक्ट्रियों पर मोटे पैसे वसूली के अतिरिक्त कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और सारी फैक्ट्री का पानी जो तालाब में इकट्ठा होता ।है वह इतना जहरीला हो चुका है। प्रदूषण इतना बढ़ चुका है। कि लगातार वहां के ग्रामीण इस आवाज को उठा रहे हैं। परंतु इस हरामखोर जालसाज मंडराई को कोई फर्क नहीं पड़ रहा और मंडराई जो अच्युतानंद मिश्र का खास है। और मोटा पैसा न केवल सदस्य सचिव के साथप्रधान सचिव और मंत्री को भी पहुंचाया जा रहा है। उसका एक रिश्तेदार अजय मिश्रा भी वहीं परकार्यरत है वह भी मोटी वसूली कर रहा है। जबकि मेघनगर जो झाबुआ जिले में आता है उसके लिए वहां का एसडीएम और कलेक्टर भी सक्षम है जो मेघनगर की ऊन फैक्ट्रियों का जो पानी तालाब में इकट्ठा होने से पूर्ण रूप से लाल हो चुका है और उसे ग्रामीणों को अनेकों बीमारियां फैला रही हैं। पशु जो पानी पीते हैं कई बार मर चुके हैं पर वहां का एडीएम एसडीएम कलेक्टर भी मोती वसूली करने के कारण कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। गुजरात में वापी जहां सबसे ज्यादा रसायन फैक्ट्रियां हैं वहां के 2 हजार से ज्यादा घातक रसायनों के टैंकर भी मध्य प्रदेश की सीमाओं में लाकर अलीराजपुर झाबुआ के नदी नालों गड्ढों तालाबों में बहाये जा रहे हैं और उसका भी पैसा मंडराई करोड़ों में वसूल कर रहा है। अर्थात प्रदूषण नियंत्रण मंडल जो मोती वसूली कर प्रदूषण फैलाव मंडल में बदल चुका है चारों तरफ सभी वसूली कर रहे हैं और यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने का मूल उद्देश्य भी उसको नष्ट करने में मिलने वाले 300 करोड़ का धन ही है जिसे इंदौर पीथमपुर के बुद्ध नागरिकों और जनता को तत्काल रोकना चाहिए।

हर कदम लूट व भ्रष्टाचार को रोक जनधन का करें सही उपयोग

30 जुलाई के बजट में करों से लूट बढ़ाने की तैयारी

75 प्र.श. जनता को नहीं मिलता शुध्द जल, 35 प्र.श. को जल ही नहीं फिर भी वसूली, बोरिंग पर प्रतिबंध

इंदौर जिला व नगरीय प्रशासन के लिए विकास व जन सुविधाओं के नाम लूट भ्रष्टाचार डकैती की प्रयोगशाला का अड्डा है। जिले में जितने भी एडीएम एसडीएम कलेक्टर निगम आयुक्त आते हैं। सब मोती रॉयल्टी पर डकैती डालने के लिए ही बैठ जाते हैं ऑन इसीलिए यह सभी प्रकार की हर कदम पर भारी भ्रष्टाचार करते हैं इसका सीधा उदाहरण है। मेट्रो ट्रेन जो 25000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इंदौर में 20 साल में भी उसकी लागत तो दूर चालन खर्च भी नहीं निकल सकेगा। परंतु उसको बनाने का मूल उद्देश्य शिवराज का केवल अपने मित्र दिलीप सूर्यवंशी को मोटा ठेका दिलवा कर मोटी कमाई करवाना था बदले में शहर की जनता पर पिछले10 साल से लगातार उसके निर्माण कार्य में बार-बार सड़कों परयातायात प्रवर्तन को झेल कर परेशान हो रही है। कईयों की मौत हो चुकी है कई उसके लिए लगाई गई टीन शेड में उचित व्यवस्थाएं ना होने के कारण घुसकर अपनी जान गंवा चुके हैं। परंतु 2020 तकपरियोजना को पूरा होने का जो वादा किया गया था सन 2024 में भी अभी अधूरी है और नई-नई परियोजनाओं की नीति तैयार होने लाइन डालने बोतल के अंदर ट्रेन चलाने के लिए गुफाएं बनाने का काम बनाने के नाम पर अगले सन 2040 तक जनता को और रहवासियों को अन्य के प्रकार के कष्ट भुगतें के लिए तैयार रहना ही होगा क्योंकि डकैतों को जितना काम बढेगा लागत बढ़ेगी उतनी मोटी कमाई होगी। यह सब बेबी अच्छी तरीके से जानते हैं की इंदौर में मेट्रो ट्रेन को प्रतिदिन एक लाख यात्री मिलना अगले 20-25 सालों में भी संभव नहीं होगा। जिसके कारण पूंजी पर लगा ब्याज जो प्रतिदिन लगभग 10 करोड रु से ज्यादा होगा। नहीं निकाल पाएंगे। वही हाल निगम केघर भ्रष्ट महा धूर्त इंजीनियरो और पुलिस की यातायात विभाग में छोटी ग्वालटोली मधु मिलन सिनेमा के पास जो नया यातायात सुधारने का प्रयोग किया था वह और बिगड़ गया और करोड़ों पर खर्च होने के बाद पिछले साल भर से जनता परेशान अलग हो रही है आखिर उन सब की लागतऔर जनता की परेशानियों की वसूली निगम आयुक्त महापौर कलेक्टर व जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन से क्यों नहीं की जाती। पर इन महा मक्कार सुकरो को इसे कोई फर्क नहीं पड़ता जनता परेशान हो तो हो जनधन डुबे तो डुबे। यह हरामखोर भ्रष्ट तो सारा भार अपनी भ्रष्टाचार लूट डकैती अय्याशी मौज मस्ती सबके खर्च

टैक्स का बोझ • बिना एमआईसी में प्रस्ताव आए भाजपा कोर ग्रुप ने ले लिया बड़ा फैसला, आम जनता पर जल्द थोपा जाएगा भार

जलकर; भोपाल में 30, ग्वालियर में 143 रु. महीना, इंदौर में 15 दिन के 200 रु., यह प्रदेश में पहले ही सबसे ज्यादा, अब इसे भी बढ़ाकर 300 रु. करेंगे

2.88 लाख वैध नल कनेक्शन शहर में

50 हजार अवैध कनेक्शन हैं

112 टंकियां पानी की तैयार हो चुकी

100 शिकायतें रोज पानी से जुड़ी

20 मिनट ही नल चलते हैं कुछ इलाकों में

6.5 लाख संपत्तिकर खाते हैं शहर में

प्रदेश में भोपाल में सबसे सस्ता पानी

शहर	जलकर	दिन	कचरा शुल्क
इंदौर	200 रु.	15	150 रुपए/ महीना
भोपाल	30-80 रु.	30	360-720 रुपए/ वर्ष
ग्वालियर	143 रु.	30	20 से 30 रुपए/ महीना
जबलपुर	170 रु.	30	30 रुपए/ महीना

व्यवस्था हमेशा कठघरे में ही रही... याचिका भी लग चुकी है हाई कोर्ट में

पहला मामला नहीं है... ऐसे ही गुपचुप तरीके से संपत्तिकर बढ़ाया था

जनता की जेब पर डालने के लिए जल संपत्ति सफाई प्रकाश आदि के करों की दरों को बढ़ाकर जनता से वसूलेंगे।

प्रतिदिन शहर के दैनिक समाचार पत्रों में निगम के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार जलशा लूट डकैती की खबरें लगातार छप रही है ना ढंग से सफाई होती है ना सड़के ढंग की होती हैं। 35% शहर को तीन चरण नर्मदा के लाने के बाद भी हर दिन पर्याप्त 60 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से जैसा की देश की सरकार के आका विश्व घातक संगठन की विश्व व्यापी निर्देशिका है के अनुसार पानी नहीं मिलता। यहां सामान्यतः 2 दिन में एक बार आधा घंटे पानी दिया जाता है अर्थात महीने में मात्र 7:30 घंटे जिसका बिल पहले ही रु. 300 से ज्यादा वसूला जा रहा है 35% शहर को पानी नहीं मिलता इसके बावजूद भी बिल थोपे जाते हैं और जबरदस्ती वसूल की जाती है अन्यथा गुलजारी करने के बाद में बिल न भरने पर उसकी वसूली आपकी संपत्ति को बैंच कर करने की डकैतों ब्लैक मेलरों की तरह धमकी दी जाती है। तिलक नगर विस्तार 47 मेरी मां का घर है जहां पिछले10 सालों से पानी नहीं पहुंचता पर बिल अवश्य पहुंचता है। जिसकी शिकायत सन 2012-13 से लगातार संगीत श्रीवास्तव को गर्मियों में बोरिंग के बैठ जाने के कारण हर वर्ष करता हूं। परंतु वह भी 15 सालों से इंदौर में जमा घोर भ्रष्ट जालसाज कुछ नहीं कर सका। आप देखिए 540 एम एलडी पानी में से 450 एम एलडी पानी इंदौर में आ रहा है। परंतु भास्कर के अनुसार ही 35% जनता को पुराने इंदौर में जल नहीं मिल रहाजो की दूसरी तरफ वही जल रेडियो कॉलोनी में जहां सभी सरकारी अधिकारियों के निवास हैं। 24 घंटे बहता रहता है। जनता को गाड़ी ना धोने का पाठ पढ़ाया जाता है परंतु वहां पर साहब लोगों की गाड़ियां नर्मदा के जल से धोई जाती हैं। जब दूसरी और तीसरी परियोजना बनाई जा रही थी तब भी है संजीव श्रीवास्तव यहीं पर था और नगर निगम आयुक्त कलेक्टर ने भू व कॉलोनी माफिया के इशारे पर नाच कर देश के बड़े भू कॉलोनी माफियाओं पूंजीपतियों की बनी कॉलोनियों में बाईपास, रिंग रोड, सुपर कारीडोर की व अन्य सैकड़ों कालोनियों में आपूर्ति कर दी गई। परंतु पुराने शहर की जनता वहीं जल के लिये ताकती रह गई। दूसरीतरफ पुरानी 75 प्रतिशत शहर में जो पुरानी पाइपलाइन डाली हुई हैं। अधिकांश सड़ चुकी हैं। जिन में फूटी हुई नालियों का मिला स्वास्थ्य घातक पानी आ रहा है। यह समाचारहर दिन दैनिक समाचार पत्रों में पिछले 15 वर्षों से छाप रहे हैं। परंतु किसी को कोई चिंता नहीं और पूरे शहरका अकेला कार्यपालन यंत्री संजीव श्रीवास्तव तो तो लाइन में फूटएन मरम्मत करवाने के साथ-साथ 5 दिन के सप्ताह में से 4 दिन कलेक्टर की कमिश्नर की भोपाल की के प्रधान सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय, नगरीय प्रशासन की विडियो कांफ्रेंसिंग में ही व्यस्त रहता है। जबकि इतने बड़े शहर में 36लाख की आबादी के हिसाब से 4 कार्यपालन, 50 सहायक, 300 उप यंत्री होना चाहिये। की अपेक्षा 1 कार्यपालन 4-5 सहायक 12-15 उपयत्री ही कार्यरत हैं। तो जब जनता को हर दिन प्रति व्यक्ति 60 लीटर पानी नहीं दे सकते। तो जलकर बढ़ाने की जुरूरत क्यों की जा रही है जो भास्कर ने छापा।

क्या जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंक

जमीन हड़पने नाकामियों से ध्यान भटकने स्वपोषित नाटक

पुलवामा की तरह लगातार आतंकी हमले, दोनों के मुंह बंदपाकिस्तान से तो व्यापार कर रहे हैं

मोदी कार्यकाल 3 में 1 जुलाई 2024 को जिस प्रकार से राहुल ने भरी संसद में मोदी की वाचालता हिंदुत्व अजैविक जन्म मंगलसूत्र लूट लेंगे, मुजरे की असभ्य भाषा पर पर पहली बार सटीक तरीके से भद्र वाक्राक्रमण किया उससे काफी बौखलाए हुए हैं। और वह नाकामी को छुपाने विदेशी यात्राओं पर जाने के साथ-साथ, कश्मीर मेंस्वयं आक्रमण को पोषित कर रहे हैं बेशक यह अजूबा लग सकता है। क्योंकि पाकिस्तान अभी अपने आंतरिक चुनावी जातीय दंगों आर्थिक कंगाली की गृह कलहों में भारी बुरी तरह से उलझा हुआ है। दूसरी तरफ मोदी और अमित शाह अब अपनी नाकामियों कुकर्मों भ्रष्टाचार जलसा जिओ से ध्यान भटकने के लिए 24 घंटे भारत केसमाचार माध्यमोंटीवी चैनल और प्रिंट मीडिया में पाकिस्तान का नाम लेना बंद कर दिया है क्योंकि उनसे उनका बड़ा लंबा व्यापार चल रहा है दूसरी तरफ अडानी भारत की और खासतौर से मध्य प्रदेश की 20000 मेगावाट बिजली जो 10 से 12000 करोड रुपए प्रति माह की होती है। चोरी करके पाकिस्तान को बेंच रहा है।

अनेकों व्यापार पाकिस्तान से चल रहे हैं और भारत के मोस्टफेवरेट नेशन की लिस्ट में पाकिस्तान पहले नंबर पर है अब ऐसी स्थिति में यह उम्मीद करना कि पाकिस्तान इन सारी परेशानियों को जलते हुए भारत में जम्मू कश्मीर में आतंकी आक्रमण करेगा शायद निरर्थक है यह सारे आक्रमण स्वयं पुलवामा अटैक की तरह मोदी साहब संचालित जनता का ध्यान भटकने के लिए करवाई जा रहे हैं और हमारे सैनिकों को जानबूझकर मंगवाया जा रहा है जैसे पहले 44 सैनिक मरवा दिए गए थे।

पुतिन की फिर परमाणु हथियार बनाने की धमकी

पेज 1 का शेष

पुतिन ने कहा, 'यह स्थिति हमें शीत युद्ध की घटनाओं की याद दिलाती है, जो यूरोप में अमेरिकी पर्शिंग मध्यम दूरी की मिसाइलों की तैनाती से जुड़ी थी।' शीत युद्ध के चरम पर 1980 के दशक में अमेरिका ने पश्चिमी जर्मनी में अमेरिकी पर्शिंग बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात की थीं। जर्मनी के पुनः एकीकरण से लेकर 1990 के दशक तक अमेरिकी मिसाइलें वहां तैनात रहीं। लेकिन शीत युद्ध की समाप्ति के बाद, मास्को से खतरा कम होने के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूरोप में तैनात मिसाइलों की संख्या में काफी कमी कर दी। क्रेमलिन ने जुलाई के मध्य में ही चेतावनी दे दी थी कि प्रस्तावित अमेरिकी तैनाती का मतलब होगा कि यूरोपीय राजधानियां रूसी मिसाइलों का लक्ष्य बन जाएंगी। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने एक सरकारी टीवी संवाददाता से कहा, 'हम शीत युद्ध की ओर लगातार कदम बढ़ा रहे हैं। प्रत्यक्ष टकराव वाले शीत युद्ध के सभी लक्षण वापस आ रहे हैं।' हम दर्पण उपाय अपनाएंगे': पुतिन ने जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइलों की तैनाती के खिलाफ अमेरिका को चेतावनी दी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को अमेरिका को चेतावनी दी कि यदि वाशिंगटन जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात करता है तो रूस भी पश्चिम की मारक क्षमता के भीतर ऐसी ही मिसाइलें तैनात कर देगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 10 जुलाई को कहा कि वह दीर्घकालिक तैनाती की तैयारी के तहत 2026 से जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइलों की तैनाती शुरू कर देगा, जिसमें एसएम-6, टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें और विकासात्मक हाइपरसोनिक हथियार शामिल होंगे। पूर्व शाही राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी नौसेना दिवस के अवसर पर रूस, चीन, अल्जीरिया और भारत के नाविकों को संबोधित करते हुए पुतिन ने अमेरिका को चेतावनी दी कि इस कदम से शीत युद्ध शैली का मिसाइल संकट पैदा होने का खतरा है। पुतिन ने कहा, 'ऐसी मिसाइलों की हमारे क्षेत्र में लक्ष्य तक उड़ान का समय, जो भविष्य में परमाणु हथियारों से लैस हो सकती हैं, लगभग 10 मिनट होगा।' 'हम संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और दुनिया के अन्य क्षेत्रों में उसके उपग्रहों की कार्रवाइयों को ध्यान में रखते हुए तैनाती के लिए समान कदम उठाएंगे।' पुतिन, जिन्होंने 2022 में यूक्रेन में अपनी सेना भेजी थी, इस युद्ध को पश्चिम के साथ ऐतिहासिक संघर्ष का हिस्सा बताते हैं, जिसके बारे में उनका कहना है कि 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद पश्चिम ने मास्को के प्रभाव क्षेत्र पर अतिक्रमण करके रूस को अपमानित किया था। यूक्रेन और पश्चिमी देशों का कहना है कि पुतिन साम्राज्यवादी शैली में ज़मीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने रूस को हराने की कसम खाई है, जो वर्तमान में क्रीमिया सहित यूक्रेन के लगभग 18इ हिस्से और पूर्वी यूक्रेन के चार क्षेत्रों के कुछ हिस्सों को नियंत्रित करता है। रूस का कहना है कि ये भूमि, जो कभी रूसी साम्राज्य का हिस्सा थी, अब पुनः रूस का हिस्सा है और इसे कभी वापस नहीं दिया जाएगा। रूसी और अमेरिकी राजनयिकों का कहना है कि उनके राजनयिक संबंध 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट से भी बदतर हैं, तथा मॉस्को और वाशिंगटन दोनों ने तनाव कम करने का आग्रह किया है, जबकि दोनों ने तनाव बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए हैं।

हरियाली अमावस्या

शुभ फलों की प्राप्ति के लिए जरूर करें ये काम

हिन्दू पंचांग के अनुसार, श्रावण माह की अमावस्या तिथि को हरियाली अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। हरियाली अमावस्या को अत्यन्त शुभ माना गया है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि सावन में हरियाली अमावस्या कब मनाई जाएगी और इस दिन क्या उपाय करने चाहिए।

हरियाली अमावस्या का मुहूर्त

सावन माह की अमावस्या तिथि 03 अगस्त, 2024 को दोपहर 03 बजकर 50 मिनट पर शुरू हो रही है। साथ ही यह तिथि 04 अगस्त, 2024 को दोपहर 04 बजकर 42 मिनट तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार सावन की हरियाली अमावस्या रविवार, 04 अगस्त को मनाई जाएगी।

जरूर करें ये काम

हरियाली अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन को पेड़-पौधे लगाने सबसे अच्छा समय माना जाता है। ऐसे में आप इस तिथि पर आम, आंवला, केला, नींबू, तुलसी, पीपल, बरगद और नीम आदि लगा सकते हैं। इससे साधक पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है।

शिव पूजन से होगा लाभ

हरियाली अमावस्या के दिन पति-पत्नी को मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से शादीशुदा जीवन में खुशहाली बनी रहती है। इसके साथ ही हरियाली अमावस्या पर दूध में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। साथ ही ॐ नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे महादेव प्रसन्न होते हैं।

पितृ दोष से मिलेगा छुटकारा

हरियाली अमावस्या के दिन महादेव को आक या मदार के सफेद फूल चढ़ाने से पितृ दोष की समस्या से मुक्ति मिल सकती है। इसके साथ ही अमावस्या पर पितरों के निमित्त सरसों के तेल का दीपक भी जरूर जलाना चाहिए।

हरियाली अमावस्या का महत्व

सावन की अमावस्या को हरियाली अमावस्या इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यह समय पौधे लगाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। बारिश की वजह से चारों तरफ हरियाली होती है और प्रकृति सुंदर दिखती है। इस समय बारिश के कारण धरती पर चारों ओर हरियाली छाई रहती है और प्रकृति की सुंदरता देखते ही बनती है। हरियाली अमावस्या नवग्रह और पितरों की शांति के लिए भी बहुत उत्तम मानी जाती है क्योंकि हरियाली अमावस्या पर विशेष पूजा और दान-पुण्य करके नवग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को शांत किया जाता है।

॥ पितृ चालीसा ॥

॥ दोहा ॥
हे पितरेश्वर आपको दे दियो आशीर्वाद,
चरण शीश नवा दियो रख दो सिर पर हाथ ।
सबसे पहले गणपत पाछे घर का देव मनावा जी ।
हे पितरेश्वर दया राखियो, करियो मन की चाया जी ।।

॥ चौपाई ॥
पितरेश्वर करो मार्ग उजागर,
चरण रज की मुक्ति सागर ।
परम उपकार पित्तरेश्वर कीन्हा,
मनुष्य योणि में जन्म दीन्हा ।
मातृ-पितृ देव मन जो भावे,
सोई अमित जीवन फल पावे ।
जै-जै-जै पित्तर जी साईं,
पितृ ऋण बिन मुक्ति नाहिं ।
चारों ओर प्रताप तुम्हारा,
संकट में तेरा ही सहारा ।
नारायण आधार सृष्टि का,
पित्तरजी अंश उसी दृष्टि का ।
प्रथम पूजन प्रभु आज्ञा सुनाते,
भाग्य द्वार आप ही खुलवाते ।
झुंझनू में दरबार है साजे,
सब देवों संग आप विराजे ।
प्रसन्न होय मनवांछित फल दीन्हा,
कुपित होय बुद्धि हर लीन्हा ।
पित्तर महिमा सबसे न्यारी,
जिसका गुणगावे नर नारी ।
तीन मण्ड में आप बिराजे,
बसु रुद्र आदित्य में साजे ।
नाथ सकल संपदा तुम्हारी,
मैं सेवक समेत सुत नारी ।
छप्पन भोग नहीं हैं भाते,
शुद्ध जल से ही तृप्त हो जाते ।
तुम्हारे भजन परम हितकारी,
छोटे बड़े सभी अधिकारी ।
भानु उदय संग आप पुजावे,
पांच अँजुलि जल रिझावे ।
ध्वज पताका मण्ड पे है साजे,
अखण्ड ज्योति में आप विराजे ।
सदियों पुरानी ज्योति तुम्हारी,
धन्य हुई जन्म भूमि हमारी ।
शहीद हमारे यहाँ पुजाते,
मातृ भक्ति संदेश सुनाते ।
जगत पित्तरो सिद्धान्त हमारा,
धर्म जाति का नहीं है नारा ।
हिन्दू, मुस्लिम, सिख,
ईसाई सब पूजे पित्तर भाई ।
हिन्दू वंश वृक्ष है हमारा,
जान से ज्यादा हमको प्यारा ।
गंगा ये मरुप्रदेश की,
पितृ तर्पण अनिवार्य परिवेश की ।
बन्धु छोड़ ना इनके चरणाँ,
इन्हीं की कृपा से मिले प्रभु शरणा ।
चौदस को जागरण करवाते,
अमावस को हम धोक लगाते ।
जात जडूला सभी मनाते,
नान्दीमुख श्राद्ध सभी करवाते ।
धन्य जन्म भूमि का वो फूल है,
जिसे पितृ मण्डल की मिली धूल है ।
श्री पित्तर जी भक्त हितकारी,
सुन लीजे प्रभु अरज हमारी ।
निशिदिन ध्यान धरे जो कोई,
ता सम भक्त और नहीं कोई ।
तुम अनाथ के नाथ सहाई,
दीनन के हो तुम सदा सहाई ।
चारिक वेद प्रभु के साखी,
तुम भक्तन की लज्जा राखी ।
नाम तुम्हारो लेत जो कोई,
ता सम धन्य और नहीं कोई ।
जो तुम्हारे नित पाँव पलोटत,
नवों सिद्धि चरणा में लोटत ।
सिद्धि तुम्हारी सब मंगलकारी,
जो तुम पे जावे बलिहारी ।
जो तुम्हारे चरणा चित्त लावे,
ताकी मुक्ति अवसी हो जावे ।
सत्य भजन तुम्हारो जो गावे,
सो निश्चय चारों फल पावे ।
तुमहिं देव कुलदेव हमारे,
तुम्हीं गुरुदेव प्राण से प्यारे ।
सत्य आस मन में जो होई,
मनवांछित फल पावें सोई ।
तुम्हरी महिमा बुद्धि बड़ाई,
शेष सहस्त्र मुख सके न गाई ।
मैं अति दीन मलीन दुखारी,
करहुं कौन विधि विनय तुम्हारी ।
अब पितर जी दया दीन पर कीजै,
अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजै ।

॥ दोहा ॥
पित्तरों को स्थान दो, तीरथ और स्वयं ग्राम।
श्रद्धा सुमन चढ़ें वहां, पूरण हो सब काम।
झुंझनू धाम विराजे हैं, पित्तर हमारे महान।
दर्शन से जीवन सफल हो, पूजे सकल जहान।।
जीवन सफल जो चाहिए, चले झुंझनू धाम।
पित्तर चरण की धूल ले, हो जीवन सफल महान।।

टेंशन में आती है सिगरेट की याद इस तरह से छोड़ें ये गंदी आदत

घर में किसी बात पर बहस हुई नहीं कि सिगरेट पीने की याद आती है। ऑफिस में काम का प्रेशर बढ़ा नहीं कि मन करता है दो तीन कश मार ही लिए जाएं। ऐसा आपके साथ होता है तो आप कोई अजूबा नहीं हैं। अधिकांश लोग स्ट्रेस मैनेज करने के लिए या स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए सिगरेट स्मोकिंग को सबसे आसान और अच्छा जरिया समझते हैं। उस वक्त तो सिगरेट का धुआं आपको ये अहसास करवा देता है कि आपने हर फिक्र को धुएं में उड़ा दिया है। लेकिन हकीकत ये होती है कि सिगरेट आपको रिलेक्स करने की जगह आपके हार्ट रेट को बढ़ा देती है। सिर्फ इतना ही नहीं ज्यादा सिगरेट पीने वालों के चेहरे पर रिंकल्स यानि कि झुर्रियां भी जल्दी आती हैं।

गहरी सांसें लें

रोज सुबह उठ कर गहरी सांस लेने की आदत डालें। कम से कम तीन बार नाक से गहरी सांस लें। हर बार सांस को धीरे-धीरे मुंह से छोड़ें। डीप ब्रीथ की ये आदत दिमाग की क्षमता बढ़ाती है जिससे स्ट्रेस झेलने की सहनशक्ति भी बढ़ती है।

भरपूर नींद लें

शुरुआत में स्मोकिंग छोड़ने का असर दिमाग पर भी पड़ सकता है। जिसे शांत रखने के लिए भरपूर नींद लेना जरूरी है। स्ट्रेस और स्मोकिंग दोनों से उबरने की कोशिश है तो रोजाना कम से कम आठ घंटे की भरपूर नींद लें। इससे दिमाग रिलेक्स रहेगा।

सही डाइट, सही एक्सरसाइज

सही खाना और सही एक्सरसाइज भी स्मोकिंग की आदत को कम करने में मदद करती है। आपके शरीर में जितने टॉक्सिन्स जमा होंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रेस होगा। सिगरेट पीने से टॉक्सिन्स कभी कम नहीं होते। इस आदत को बेलेंस डाइट के साथ बदलें। इसके अलावा एक्सरसाइज करें ताकि पसीने के साथ शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स भी बह जाएं।

कैफिन की खुराक

कैफिन की खुराक भी कम करना जरूरी है। चाय कॉफी जिन चीजों में कॉफिन होता है उन्हें कम से कम पिएं। कैफिन आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा सकता है। इसलिए उनकी खुराक में कमी या फिर उनकी आदत को छोड़ देना ही मुनासिब है।

शौक में डूबें

ऐसे किसी काम में मन लगाएं जिसे करना आपको बहुत पसंद है या फिर वो आपकी हॉबी है। ये डांस, गाना, पेंटिंग कुछ भी हो सकती है। आपका शौक आपको स्ट्रेस से राहत देगा और स्मोकिंग की याद भी नहीं आएगी।

लोगों से मिलना-जुलना शुरू करें

स्ट्रेस और स्मोकिंग की वजह से लोगों से कन्नी काटने लगे हों तो ये आदत भी छोड़ दीजिए। अब लोगों से दूर होने की जगह उनसे मिलना जुलना और बातें करना शुरू कर दें। अपने फ्रेंड्स से फैमिली के लोगों से या ऑफिस के साथियों से जीभर कर बात करें। लेकिन उन लोगों से दूरी बनाकर रखें जो आपको फिर से स्मोकिंग के लिए उकसाएं।

सावन में सोमवार व्रत के दौरान

जरूर रखें इन बातों का ध्यान

सावन को सोमवारी का महत्व क्या होता है, यह बताने की जरूरत नहीं है। भगवान शंकर की असीम कृपा पाने के लिए भक्तजन सावन के हर सोमवार को उपवास रखते हैं और भोलेनाथ को जल और बिल्व पत्र अर्पित करते हैं। हालांकि, नीलकंठ को प्रसन्न करने के लिए रखे व्रत के दौरान आपको कुछ खास बातों का ख्याल रखना चाहिए, जिससे आप भगवान शिव की पूजा भी कर सकें और आपकी सेहत भी बनी रहे। आइए जानें, सावन के सोमवार व्रत करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए।

तला भुना न खाएं

अक्सर लोग उपवास वाले दिन व्रत खोलते समय कुछ तला भुना खा लेते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा करने से आपको गैस और एसिडिटी की समस्या हो सकती है। इसलिए तले भुने खाने से परहेज करें। इनकी जगह साबूदाने की खीर, शीरा जैसी चीजें खा सकते हैं।

पानी पीते रहें

सावन का महीना अपने साथ बारिश की फुहार लेकर आता है, जिससे गर्मी से तो राहत मिलती है, लेकिन उमस काफी बढ़ जाती है। इसके कारण पसीना आता है और डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसलिए पानी पीते रहना जरूरी है, नहीं तो चक्कर आ सकते हैं और पूजा का सारा आनंद किरकिरा हो सकता है।

फलाहार करें

सावन के सोमवार व्रत में अन्न खाना मना होता है, लेकिन खाली पेट ज्यादा समय तक रहने से एसिडिटी और गैस बन सकती है। इसलिए इस परेशानी से बचने के लिए फलाहार जरूर करें। पपीता, खीरा, केला जैसे फल खाने से आपको एनर्जी भी मिलेगी और आपका व्रत भी पूरा हो जाएगा।

ज्यादा शारीरिक मेहनत न करें

उपवास के दौरान ज्यादा शारीरिक मेहनत करने से आप जल्दी थक सकते हैं। इसके कारण बाकी का दिन बिताने में आपको तकलीफ हो सकती है और बार बार भूख भी लग सकती है, जिसके कारण आपके व्रत से आपका ध्यान भटक सकता है। इसलिए ज्यादा शारीरिक मेहनत वाला काम न करें।

व्रत का खाना खाएं

व्रत के दौरान कुछ खास पकवान, जैसे कुट्टू के आटे की रोटी, साबुदाना खीर, आलू-दही, हल्वा आदि खाया जा सकता है। इसलिए अगर आपको लो बीपी या गैस बनने की समस्या रहती है, तो अपनी इन चीजों का सेवन कर सकते हैं। इन्हें खाने से आपको एनर्जी भी मिलेगी और तबियत भी नहीं बिगड़ेगी, जिससे आप अपना ध्यान भगवान शंकर की आराधना में लगा सकते हैं।

उन्नति पाने के कुछ खास टोटके

सनातन धर्म में वास्तु शास्त्र का अधिक महत्व बताया गया है। ऑफिस में दिनभर अधिक मेहनत करने के बाद भी मनचाहा अप्रेजल नहीं मिल पाता है। अगर आप भी इस तरह की परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो ऐसे में आप वास्तु शास्त्र में बताए गए चमत्कारी उपायों को जरूर आजमाएं।

करें ये टोटके

अगर आप इंटरव्यू में पास नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में इंटरव्यू वाले दिन सुबह नहाने वाले पानी में हल्दी मिलाकर स्नान करें। इसके बाद वस्त्र धारण कर पूजा करें और 11 अगरबत्तियों को जलाएं। इसके बाद इंटरव्यू के लिए जाएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से इंटरव्यू में सफलता प्राप्त होती है।

नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए रविवार के दिन गाय को गेहूं और गुड़ खिलाएं। इसके बाद जल पिलाएं और पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। इस टोटके को लगातार 5 या 7 रविवार तक करें। वास्तु के अनुसार, ऐसा करने से जॉब में प्रमोशन होता है। साथ ही अच्छा अप्रेजल मिलता है।

इसके अलावा जॉब में प्रमोशन पाने के लिए सोमवार के दिन किए जाने वाले उपाय भी बेहद फलदायी साबित होते हैं। इस दिन सफेद कपड़े में काले चावल बांधें। इसके बाद इसे मां काली को अर्पित करें। मान्यता के अनुसार, इस उपाय को करने से प्रमोशन होता है।

यदि आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो शनिवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान शनि देव की पूजा करें। साथ ही स्नान ऊं शं शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से मनचाही नौकरी मिलती है।

महिलाओं के लिए फायदेमंद है शतावरी की चाय

उम्र के अलग-अलग पड़ावों पर होने वाले हार्मोनल बदलावों का, महिलाओं के शरीर पर काफी असर होता है। शरीर में होने वाले हार्मोनल उतार-चढ़ाव के चलते, महिलाओं की मेंटल और फिजिकल हेल्थ प्रभावित होती है। इसलिए, उम्र के अलग-अलग पड़ावों पर सेहतमंद रहने के लिए, महिलाओं को डाइट और रूटीन में कुछ खास बदलाव करने चाहिए। कई हर्ब्स भी महिलाओं की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। 45 की उम्र के बाद सेहतमंद रहने और एजिंग के साइन्स को कम करने के लिए, कुछ खास चीजें कारगर हैं। एक्सपर्ट की बताए इन 2 हर्ब्स की चाय, डाइट में जरूर शामिल करें।

महिलाओं के लिए शतावरी बहुत फायदेमंद है और इसमें महिलाओं की कई बीमारियों का इलाज छिपा है। शतावरी हर्ब, हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करता है।

इससे मेनोपॉज के लक्षण भी कम होते हैं।

इसे फर्टाइल एज में भी डाइट में शामिल किया जा सकता है।

यह महिलाओं की फर्टिलिटी सुधारने में कारगर है।

इससे डाइजेशन से जुड़ी दिक्कतों से भी राहत मिलती है। इस चाय से दिमाग और शरीर रिलेक्स होता है और कमजोरी दूर होती है।

45 के बाद महिलाएं जरूर पिएं मोरिंगा की चाय

मोरिंगा एक सुपरफूड है। इसे यूं तो हर उम्र की महिलाओं की डाइट में शामिल करना चाहिए। लेकिन, खासकर, 40-45 की उम्र में इसे जरूर खाना चाहिए। इसका सेवन कई तरीकों से किया जा सकता है। इसकी चाय भी बेहद फायदेमंद होती है। इसमें आयरन, कैल्शियम और अन्य कई जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं। यह चाय मेटाबॉलिज्म को सुधारती है। साथ ही, स्ट्रेस, एंग्जायटी और मूड स्विंग्स को भी कम करती है। यह एजिंग के साइन्स को भी कम करती है।

यह चाय, 45 की उम्र के बाद होने वाले जोड़ों के दर्द को कम करने के लिए भी बेहद फायदेमंद है। 45 से अधिक उम्र की महिलाएं, इन 2 चाय को डाइट में जरूर शामिल करें।

साप्ताहिक समय माया

मध्यमवर्गीय को निचोड़ जालसाज पूंजीपतियों को बढ़ाना

पेज 1 का शेष

इस तरह आपको प्रॉपर्टी पर तो 60 हजार का फायदा मिल गया लेकिन सीआईआई के मुताबिक गणना करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी की खरीद कीमत 1.4 लाख मानी जाएगी और आपका फायदा सिर्फ 20 हजार का ही कैलकुलेट होगा और इसी 20 हजार पर आप 20 प्रतिशत की दर से कैपिटल गेन टैक्स भी देंगे। यानी कुल चार हजार रुपए।

जबकि नए नियम के मुताबिक आपको पूरे 60 हजार रुपये पर 12.5 प्रतिशत की दर से टैक्स देना होगा। यानी जिस प्रॉपर्टी को बेचने पर पहले आप 4000 रुपए टैक्स चुकाते उसी पर अब आपको 7,500 रुपये चुकाने पड़ेंगे। यानी अब आपको लगभग दोगुना अंतर आ गया है।

इतना ही नहीं बैंक एफडी, बॉन्ड, गोल्ड और म्यूचुअल फंड में निवेश पर भी अब मंहगाई बढ़ने से हुए नुकसान पर राहत नहीं मिलेगी। सरकार ने LTCG पर टैक्स की दर को 10 से 12.5 प्रतिशत तो की ही है शॉर्ट टर्म कैपिटलगेन की दर भी 15 से बढ़ा कर 20 प्रतिशत कर दी है। इससे आपकी एसआईपी से हो रही छोटी बचत पर मिलने वाले लाभ कम हो जायेंगे। अब अगर शेयर मार्केट चढ़ता है तो सरकार आपके फायदे में तो हिस्सा बांटने आ जायेगी। लेकिन बाजार गिरता है तो नुकसान निवेशक अकेले झेले।

बैंकों में जमा करने पर, ब्याज पर, निकालने पर हर प्रकार के कर लगाने से स्वाभाविक सी बात है की मिडिल क्लास बैंकों में भी धन जमा करने से बचने लगा है और यह बचत की दर जो सन 2014 के पहले 11.5% से ज्यादा थी वह घटकर 5.3% पर आ गई। इस पर अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक निधि जो कि अमेरिका का अंतरराष्ट्रीय भारतीय बनियों की तरह का साहूकार है। ने भी चिंता व्यक्त की है। क्योंकि देश की यही घरेलू बचत जो बैंकों में पहुंचती है छोटे उद्योग व्यवसाय से लेकर बड़े-बड़े पूंजी, उद्योग पतियों के काम आती है। जो रोजगार का साधन बनती है।

संघ की संस्कृति में दीक्षित भाजपा सरकार में वित्त मंत्री कर्ण प्रिय शब्दों के मकड़जाल के साथ 2024 का बजट पेश करते हुए आगे करना क्या चाहती हैं। यही बात छुपा ली गई है। मूल लक्ष्य जिसे साधने की वित्त मंत्री ने एक घंटा 20 मिनट के बजट भाषण में कसरत की है। वह जनता के जेब से किसी न किसी बहाने पैसा निकाल कर कॉरपोरेट इंडिया की तरफ प्रवाह को तेज करना था। इसके लिए उन्होंने असफल कसरत की है। जो संक्षेप में इस प्रकार है।

कुछ तथ्य- वर्तमान का यथार्थ।

महंगाई -खाद्य महंगाई 9.4 प्रतिशत बढ़ी है। सब्जी 29.32 प्रतिशत, अनाज 8.75 प्रतिशत, दलहन 16.6%, दूध 7 प्रतिशत के आसपास।

बेरोजगारी-वृद्धि दर 9.2 प्रतिशत, शिक्षित और उच्च शिक्षित बेरोजगारी 23% से 46% के बीच में है।

बचत दर-आज तक के इतिहास की सबसे कम 5.3 प्रतिशत।

गोल्ड लोन-आईएमईआई बढ़ता जा रहा है।

प्राइवेट कंजम्पशन-58% पर लंबे समय से ठहरा है। सामान्य आदमी की उपभोग क्षमता घटी है। जिससे बाजार का संकट तीव्र हुआ है।

एआई-आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रोजगार तेजी से घट रहा है। सरकार के अनुसार बेरोजगारी दर 6,7% जबकि यह 28% से ज्यादा ।

सवाल जनता से यह है कि जो आपके पास है, उसे किस तरह से बचा के रखें, क्योंकि मुसीबत आने वाली है।

आयकर– मामूली छूट - 17500 रुपए। 3 लाख से 10 लाख के बीच सालाना कमाने वालों के लिए, जो सरकार दे रही है

जीएसटी दर में कोई परिवर्तन नहीं।

सरकारी टैक्स-27 लाख 28 हजार करोड़ से बढ़कर 31 लाख 25 हजार करोड़ हो गया है। 15% की बढ़ोतरी।

इस वर्ष टैक्स से चार लाख करोड़ की अतिरिक्त वसूली। जीएसटी, इनकम टैक्स, पेट्रोल, डीजल टैक्स यथावत।

सरकार को 12 लाख करोड़ बजट से ऋण भुगतान में देना है। इसके लिए सरकार 16 लाख करोड़ बाजार से (देसी विदेशी) ऋण लेने जा रही है। वैसे ही विदेशी ऋण सर्वकालिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास। जिसके ब्याज की वापसी शुरू होने जा रही है। कंपनी टैक्स से निजी आयकर ज्यादा है। जो 13 लाख 87 हजार करोड़ है।

64% जीएसटी आम उपभोक्ता के जेब से आती है। कॉर्पोरेट कुल जीएसटी संग्रह का 23% देते हैं। पिछले वर्ष 10 लाख 44 हजार करोड़ से बढ़कर इस वर्ष 11 लाख 88 हजार करोड़ हो गया। यानी सरकार ने 1,40 लाख करोड़ जनता की जेब से निकाल लिया।

खर्चा –

रक्षा व्यय- पिछले साल 4.55 लाख करोड़ था। जो इस साल घटकर 3 लाख 55 हजार करोड़। यानी देश की सुरक्षा,सेना पर 1 लाख करोड़ रूपया इस वर्ष कम खर्च होगा। भारतीय सेना के पराक्रम का गुणगान और तेज हो जाएगा। याद रखें अग्निवीर। बढ़ते आतंकी हमले। चीन पाकिस्तान सीमा पर बढ़ती असुरक्षा के बीच बजट में कटौती।

फर्टिलाइजर सब्सिडी-1.89 हजार करोड़ से घटकर 1.64 हजार करोड़। यानी 25 हजार करोड़ की कमी। किसान पूजा पाठ पर ज्यादा ध्यान लगाए।

फूड सब्सिडी– पिछले वर्ष 2.12लाख करोड़ इस वर्ष 2. 5 लाख करोड। 7 हजार करोड़ की कमी।

कृषि बजट-1,44 हजार करोड़ से बढ़कर एक 1, 51 हजार करोड़। 6000 करोड़ की वृद्धि। जो शक्ल घरेलू उत्पादका ढाई% है। किसान सम्मान निधि 6 साल बाद भी 60 हजार करोड़ पर स्थिर। विदेश मंत्रालय का आबंटन -2 9हजार करोड़ से घटकर 22हजार करोड़ रुपए्। 7 हजार करोड़ की कमी। लगता है विश्व गुरु और विश्व नेता बनने की योजना स्थगित हो गई है।

शिक्षा-

समग्र शिक्षा अभियान 2 साल पहले 33.5 हजार करोड़ था। जो अब घटकर 33.3 हजार करोड़ हो गया है। शिक्षा सुधार उच्च शिक्षा और शोध तथा अन्य विषयों के लिए बजट में कोई चर्चा नहीं की गई है। सिर्फ शिक्षा ऋण से शिक्षा की गाड़ी आगे चलनी है। शिक्षा ऋण की माफी या उसमें किसी रियायत पर चर्चा नहीं है। प्रधानमंत्री पोषण स्कीम 1268 करोड़ से घटकर 1240 करोड़ हो गई है।

आयुष्मान भारत 7200 करोड़ से 140 करोड़ जनता का इलाज होना है। सार्वभौम स्वास्थ्य सेवा पर न कोई बहस है न चिकित्सा व्यवस्था मे सुधार की कोई योजना।

प्रधानमंत्री आवास योजना - 30 हजार करोड़ पहले था। अब 28 हजार करोड़। एक करोड़ मकान जिनकी लागत 10 लाख रुपए आएगी। बनाने की योजना है।

2022 तक सबको पक्का मकान देने की गारंटी प्रधानमंत्री पहले ही दे चुके थे। लगता है मोदी की यह गारंटी अमृत काल के पार चली गई है।

स्मार्ट सिटी -8 हजार करोड़ से घटकर 2400 करोड़। 10 वर्ष पहले से बन रहे 100 स्मार्ट सिटी के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत की गई।

मनरेगा 3 साल पहले 90 हजार करोड़ था। अभी भी 86 हजार करोड़ पर रुका है। जबकि जॉब कार्ड धारकों की संख्या बढ़ी है। वित्त मंत्री ने जॉबकार्ड धारक परिवार एक सदस्य को 1 साल में मनरेगा में 100 दिन काम देने की घोषणा की है।

अनुसूचित जनजाति विकास– 4300 करोड़। जो दो वर्ष से स्थिर है।

वात्सल्य मिशन 2 साल पहले 1472 करोड़ रुपये से शुरू हुआ था अभी भी वहीं पर रुका है।

मिशन शक्ति– 2 साल पहले 3144 करोड़। अब बढ़कर 3146 करोड़ फसल बीमा 15000 करोड़ से घटकर 14.5 हजार करोड़।

मिड डे मील, पोषण तत्व अधिकार– सब्सिडी 86000 करोड़ 22-23 में थी। 24-25 में घटकर 46000 करोड़ हो गई। यानी 40 हजार करोड़ की कमी।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना– 272 लाख करोड़ से घटकर 202 लाख करोड़। मुफ्त अनाज योजना को अगले 5 साल तक चलने की घोषणा की गई है।

पूर्वोत्तर भारत– 2490 पर करोड़ 3 साल से टिका है। पूर्वोत्तर के आठ राज्यों के लिए 8 करोड़ का वित्तीय आवंटन। पूर्वोत्तर विकास के लिए 22-23 में 50 हजार करोड़ दिया गया 5 वर्ष के लिए। प्राइवेट सेक्टर से 24000 करोड़ 2 साल में निवेश करना है।

प्रतिवर्ष 2 हजार करोड़ का खर्च सरकार और प्राइवेट से 8 हजार करोड़ लेकर पूरा किया जाएगा।

रेलवे विद्युतीकरण– 8663 करोड़ को घटा दिया गया। बाकी रेलवे पर कोई चर्चा नहीं। ट्रैक का आधुनिकीकरण सुरक्षा कवच लगाना रखरखाव नई रेल लाइन का निर्माण आदि पर बजट में कोई ठोस और स्पष्ट दिशा नहीं है। इसके लिए बजट में अलग से कुछ अभी दिखाई नहीं दे रहा है। दुर्घटनाओं की संख्या को देखते हुए सरकार की उपेक्षा चिंताजनक। साफ बात है सरकार बहुत शीघ्र रेल से अपना हाथ झाड़ लेना चाहती है। न रेलवे में खाली पड़े पदों को भरने की बात है न नए जॉब क्रिएट करने की।वस्तुत रेलवे को धीरे-धीरे निजी उद्योगपतियों के हाथ में दे देना है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी।

शेयर मार्केट– लॉन्ग टर्म गैन पर टैक्स 10% से बढ़कर 12.5% शार्ट टर्म गेन पर 15% से बढ़कर 20.5 प्रतिशत कर दिया गया है। रोजगार के अभाव में बड़ी तेजी से जो युवा पीढ़ी शेयर मार्केट की तरफ आकर्षित हुई थी। शॉर्ट टर्म में गेन में ही पैसा लगा कर रोटी-रोजी चला रही थी। अब बड़े खिलाड़ियों के हित में? इन पर भी हमला।

कस्टम ड्यूटी-कम की गई है। विदेशी निवेश पर टैक्स घटा दिया गया है। कुछ कैंसर की दवाओं पर एक्साइज ड्यूटी घटी है।बाकी चीजें यथावत हैं। इस तरह यह विकास यात्रा आगे बढ़ रही है।

एम एस एम ई– 30% जीडीपी का आता था। वह घटकर 23% पर आ गया है। लघु और मध्यम उद्योगों की जीएसटी में भागीदारी 7.5% घटी है। इनको उबराने की बजट में कोई रूपरेखा नहीं है।

कृषि– 7500 करोड़ रिसर्च पर खर्च होगा। जलवायु उपयुक्त उच्च फसल वाली किस्म को प्रोत्साहित करने के नाम पर जीएम सीड को खेती में प्रवेश कराने की तैयारी। शब्दावली थोड़ा खूबसूरत और लिरिकल है।

भूमि का डिजिटलाईजेशन– 5 करोड़ किसानों की भूमि का डिजिटलाजेशन होगा। स्पष्ट है भूमि बैंक में जमीन की वृद्धि। जो भविष्य में कॉरपोरेट घरानों को दी जा सके।

रोजगार के संकट के हाल के लिए कौशल विकास नामक फ्लॉप योजना का आलाप जारी है।

फिर वही मुद्रा लोन 10 लाख से बढ़कर 20 लाख। बिना किसी जमानत के। अब तक के मुद्रा लोन योजना की समीक्षा कहीं से पेश नहीं की गई। रोजगार के नाम पर 500 निजी कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे एक करोड़ नौजवानों को 6 महीने या 1 साल तक इंटर्नशिप देकर उन्हें रोजगार के योग्य बनाएं। सरकार इसमें 3000 कंपनियों को और 5000 इंटर्नशिप करने वाले को मासिक देगी। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है की इंटर्नशिप के बाद उन नौजवानों को कंपनियां रोजगार पर रखेंगी या नहीं। क्योंकि सरकार पहले ही कह चुकी है कि कॉरपोरेट मुनाफा तो बहुत कमा रहे हैं। लेकिन रोजगार सृजन करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। नौकरी वालों के लिए टैक्स की सीमा बढ़ने से 17500 रुपए की छूट मिली है। तथा 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है।

शेयर बाजार में 1 साल से ज्यादा अवधि तक निवेश करने वालों को 10% से बढ़कर 12:5% पर टैक्स और 1 साल की अवधि के लिए निवेश करने वालों को 15% से बढ़ाकर 20% तक टैक्स लगाया गया है। भारत में फ्लैट, सोना और जेवर खरीदने बेचने पर 12.5 प्रतिशत टैक्स। मध्य वर्ग सावन मास में पूजा पाठ का समय थोड़ा और बढ़ा दे। शांति मिलेगी।

कॉरपोरेट टैक्स में छूट। प्रत्येक एसेट के कैपिटल गैन में 12.5% टैक्स लगेगा।

विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में निवेश पर टैक्स 40% से घटाकर 35% कर दिया गया। संभवतः चीनी कंपनियों को आकर्षित करने का प्लान है। 60% आयत चीन से ही होता है। और भारत को चीन के साथ आयात-निर्यात में भारी घाटा उठाना पड़ रहा है। एफडीआई 1 साल में 62% घट गई।

कृषि और उससे संबद्ध गतिविधियों के लिए आबंटन 144214 करोड़ से घटकर 140553 करोड़ हो गया है। यह सम्पूर्ण बजट का 2.5% है। जबकि कृषि के लिए संपूर्ण बजट का तीन से चार प्रतिशत आबटित करने की मांग हो रही थी। सम्पूर्ण श्रम बल का 46% कृषि में ही लगा है। यानी कृषि 46% रोजगार का सृजन करती है।

जनजातियों के विकास का धन 4111 करोड़ से घटकर 3874 करोड़ रह गया है। समाज कल्याण में 55 हजार 80 करोड़ से घटकर 46 हजार 741 करोड़ पर आ गया है।

यह है पूरा बजट आवंटन जो मोटी-मोटा दिखाई दे रहा है। इस तरह बजट में जन कल्याण विकास मनरेगा खाद्यान्न सुरक्षा किसान सम्मान निधि मिड-डे-मील पोषणीय तत्वों के सप्लाई और समाज कल्याण से लेकर जनजातियों के लिए लगने वाले पैसे में भारी कमी देखी गई।

राजनीतिक दबाव-चुनाव में बीजेपी की हार का सदमा बजट के निर्धारण में साफ-साफ दिखाई दे रहा है। बैसाखी पर टिकी सरकार के वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बिहार और आंध्रप्रदेश के बारे में बार-बार चर्चा कर यह दिखाने की कोशिश की है कि बिहार और आंध्र प्रदेश में स्वर्ग आने वाला है। बजट में बिहार के लिए 27000 करोड़ और आंध्र के लिए 15000 करोड़ रुपए के आवंटन ने सबका ध्यान खींचा है।

यह आवंटन मूलतः इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में लगेगा। यहां भी भाजपा ने बोध गया गया राजगीर नालंदा जैसी जगहों को कनेक्टिविटी से जोड़कर यह दिखाने की कोशिश की है कि वह अपने हिंदूत्ववादी एजेंडा पर अभी भी टिकी हुई है। जबकि बिहार के पिछड़ेपन को देखते हुए बिहार में कृषि विकास के लिए सीधे पूंजी निवेश की जरूरत थी। जिसमें सिंचाई के साधनों का विस्तार नहरों की मरम्मत जलाशयों और बांधों के निर्माण द्वारा जल संग्रह के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास? के सवाल को हल करने की जरूरत थी।

भारत में सबसे ज्यादा श्रम का पलायन बिहार से ही होता है। उत्तरी बिहार जहां बाढ़ में डूब जाता है वहीं दक्षिणी बिहार सुखाड़ से पीड़ित रहता है। बिहार के समृद्धि का रास्ता बाढ़ और सुखाड़ से मुक्ति दिलाने के रास्ते से ही आगे बनता है।

बिहार में पटना को जोड़ने वाले चार एक्सप्रेस-वे के निर्माण की घोषणा कर भारत सरकार ने यह दिखाने की कोशिश की है कि वह बिहार को इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आधुनिक राज्य बनाना चाहती है।

ये सभी परियोजनाऐं? अगले 5 वर्ष की के लिए है। तब तक बिहार को मोदी सरकार बचाने के लिए बैसाखी लगाए रखना होगा। वही आंध्र प्रदेश में राजधानी के निर्माण के लिए 17 हजार करोड़ देकर केंद्र सरकार ने दूसरी बैसाखी का इंतजाम किया है। लेकिन इस प्रक्रिया में भारत सरकार यह भूल गई है कि एक विशालकाय? देश की जिम्मेदारी उसके कंधे पर है।

पूर्वोत्तर भारत की बात करते हुए बार-बार आंध्र उड़ीसा झारखंड बिहार बंगाल पर चर्चा जाकर केंद्रित हो जा रही थी। साफ बात है कि पश्चिमोत्तर भारत, उत्तर प्रदेश,

दक्षिणी भारत से हताश भाजपा ने इस आदिवासी पट्टी में अपनी जड़ें जमाने की योजना बनाई है। जहां पहले से ही आरएसएस एक सांप्रदायिक एजेंडा के साथ सक्रिय है। वह पहले भी उड़ीसा झारखंड छत्तीसगढ़ में कई बार सांप्रदायिक विध्वंस कर चुका है। उड़ीसा में नवीन बाबू को यह बात अभी भी याद है, कैसे 50 हजार से ज्यादा आदिवासी ईसाइयों को उजाड़ दिया गया था। इसलिए राजनीतिक विश्लेषकों को इसे सिर्फ भाजपा की राजनीतिक मजबूरी के रूप में नहीं देख कर उसके दूरगामी सांप्रदायिक एजेंट के विस्तार के संदर्भ में भी देखना चाहिए।

दूसरी बात कश्मीर के लद्दाख से शुरू कर पंजाब हिमाचल उत्तर प्रदेश हरियाणा राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से कन्याकुमारी तक बजट में किसी भी राज्य के बारे में कोई चर्चा एक बार भी नहीं की गई । सामान्य बात है कि भाजपा कश्मीर पंजाब हरियाणा महाराष्ट्र और दक्षिण भारत से हताश और निराश हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की हार से वह अभी तक ऊबर नहीं पाई है। हिन्दी पट्टी में अपनी पराजय को देखते हुए भाजपा और ज्यादा अलगाव वादी तथा सांप्रदायिक होती जा रही है। हालिया दिनों में हुई घटनाएं इस बात का संकेत है।

इसलिए बजट की दिशा और प्राथमिकताओं को हमें अवश्य समझना चाहिए। वैसे हमें पता है कि बेरोजगारों के सवाल, किसानों के लिए एमएसपी का सवाल, कर्ज माफी, शिक्षा स्वास्थ्य जैसे सवाल भाजपा के एजेंडे में कभी नहीं रहे और न आगे आने वाले हैं। उसकी प्रार्थनाएं बहुत स्पष्ट हैं। उसके विकास के रास्ते सांप्रदायिक विभाजन और धार्मिक एजेंट के इर्द-गिर्द ही केंद्रित रहते हैं ।

इसलिए इस बजट में फिलहाल इस तरह के खुले संकेत न होने से थोड़ी राहत तो महसूस हो ही रही है। लेकिन यह क्षणिक है। ज्यों ही भाजपा फिर से ताकतवर होगी और ज्यादा आक्रामक तथा विध्वंसक रूप में सामने आएगी। इसलिए इस देश के लोकतंत्र पसंद नागरिकों, सामाजिक- राजनीतिक कार्यकर्ताओं, मानवाधिकार से जुड़े संस्थाओं, व्यक्तियों और विपक्षी राजनीतिक दलों को भी सचेत रहने की जरूरत है और भाजपा पर दबाव बनाकर उसे बाध्य करने की जरूरत है कि वह देश के बुनियादी सवालों के समाधान के रास्ते पर वापस लौटे हालांकि भाजपा के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट से हताशा निराशा और दिशाहीनता से स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि भाजपा सरकार के भविष्य पर संकट हमेशा मंडराता रहेगा। जिससे संसद से लेकर सड़क तक जन संघर्षों की आवाज़ें बार-बार सुनाई देती रहेगी।

WHO के इशारे पर 5 करोड़ उद्योग धंधों को चौपट 25 करोड़ को बेरोजगार करने का षड़यंत्र

पेज 8 का शेष

इन सब में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा उद्योग धंधे उसे गुजराती जाहिल डकैत मोदी के कारण सदा के लिए बर्बाद हो गए और लगभग 10 करोड़ सदा के लिए जो किसी प्रकार अपना जीवन यापन अपने स्वतंत्र व्यवसाय के दम पर करते थे सदा के लिए बेरोजगार हो गए। कुछ छोटे उद्योग धंधे दुकानें बाजार जो किसी प्रकार की स्थान करके घाटी के बाद में भी चलाई जाते रहे उनको एक देश एक टैक्स के नाम पर बहुराष्ट्रीय कंपनी के इशारे पर थोपा गया भारी भरकम अत्यधिक उलझनपूर्ण जीएसटी जिसको लगे हुए 7 साल हो गए जिसके 2585 दिन में 7000 से ज्यादा उस कर प्रणाली में छोटे व्यापारियों उद्योगों धंधों को उलझाकर षड़यंत्रकारी तरीके से समाप्त करने खेल किया जा रहा है। उसके बाद में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रखेले और उनके धन से संचालित विश्व घातक संगठन के फर्जी सर्जी खांसी की बीमारी के नाम पर कोरोना के षड्यंत्र में देश और दुनिया को तालाबंदी में झोंक छोटे व मध्यमवर्गीय उद्योग धंधों व्यवसायों दुकानों बाजारों मंडियो को बंद कर देश के 15 करोड़ से ज्यादा किसानों का माल हड़पने औने पौने मैं खरीद कर एक तरफ जनता को भूख मारने और दूसरी तरफ माल पर कब्जा करके शॉपिंग मॉलस से मनमानी कीमत पर बैंचने का षड़यंत्र किया गया। सन 2000 अटल की सरकार के समय के घोर भ्रष्ट जालसाज पूंजी पतियों के इशारे पर नाचने वाले मंत्री प्रमोद महाजन व पूरे अटल मंत्रिमंडल जिसने देश के अडानी अंबानी टाटा बिरला आदि के लिए अनेकों षड्यंत्र किये। इस समय अंबानी बांधों के रिलायंस में देश में लगभग 600 शॉपिंग मॉल जो सब्जी से लेकर सभी प्रकार की खाद्य सामग्री व अन्य जनता के उपयोग की वस्तुएं बेचने के लिए शॉपिंग मॉल खोले थे। तब ही से विश्व घातक संगठन के इशारे पर नाच अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट जिसका लगभग 150 देश में खाद्य व्यवसाय कीशॉपिंग मॉल की श्रृंखला है ने खाद्य सुरक्षा वह मानक अधिनियम बनाने, थोपने लगाने का कार्य शुरू कर दिया था। जिसे मनमोहन सिंह की सरकार के समय सन 2006 में देश पर ठोक दिया उसे समय भी समय माया ने हीं सबसे पहले व्याख्या कर उसके षड़यंत्रों का प्रकाशन कर दिया था जिसके परिणाम स्वरूप उसको 5 साल तक देश पर नहीं थोपा जा सका। पर 5 अगस्त 2011 से षड़यंत्रों के खुलासा होने और देश के बाजारो में हल्ला मछली के बादतीन दिन तक 10 11 12 अप्रैल 2012 को देश बंद होने के कारण संशोधन के साथ लागू किया गया पर मोदी के आने के बाद उस कानून को उसका मूल स्वरूप में लागू करने के लिए उपरोक्त अनुसार सारे षड्यंत्र किए गए। यह पूरा देश मोदी के आने के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मोटा कमीशन खाने के कारण चंगुल में फंसाया जा रहा है।

उस खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 06 में जो मूल व्यवस्थाएं हैं उनके अंतर्गत देश के सारे बाजरो मंदिरों दुकानों को साफकर जनता को बहुराष्ट्रीय कंपनी और पूंजीपतियों के शॉपिंग मॉल के हवाले कर एक तरफ खाद्य उत्पादक किसानों की फसलों की लागत मूल्य ना दे, घाटे में पहुंच कर जमीनों पर कब्जा करने शोषण कर उनके खेतों पर कब्जा करना है तो दूसरी तरफ जनता का हर तरह से पूंजीपतियों द्वारा मनमानी कीमत पर माल बेचकर लूटने के साथ रक्त चूस कर उनको अकाल मृत्यु देने का षड्यंत्र है। इसके लिए भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय मोदी के आने के बाद जिसके अंतर्गत खाद्य पदार्थों की जांच, नियमन, गुणवत्ता आदि की आड़ में छोटे व्यापारियों उद्योगी बाजारों को खत्म करने का षड्यंत्र सतत 2014 से सफाई कैशलेस नोटबंदी जीएसटी और तालाबंदी की आड़ में तो किया ही जा रहा है साथ में उनकी दुकानों पर विश्व घटक संगठन के सारे पर खाद्य जांच चलित प्रयोगशाला की गाड़ियां हर संभाग में एक-एक दे दी गई। जो गांवों से लेकर शहरों तक दूध दही से लेकर नाश्ते चाय काफी मिठाई भोजन किराना वस्तुएं विक्रेताओं सामग्री के नमूने लेना और उसकी गुणवत्ता बताना है। परंतु इन सभी चरित खाद्य प्रयोगशाला वाहनों का न तो शासकीय गजेट में न तो नोटिफिकेशन हुआ है और नहीं मैं कोई स्थाई ड्राइवर कंडक्टर के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी, प्रयोगशाला विश्लेषक आदि की स्थाई नियुक्ति की गई है। इसलिए यह वैधानिक रूप से औचित्यहीन है। वैसे भी अधिकतर समय यह खाद्य सुरक्षा व औषधि निरीक्षक कार्यालय के सामने खड़ी ही पाई जाती हैं। जिनका मूल उद्देश्य खाद्य व्यवसायियों को चमकाना व नमूने लेने के नाम डराना धमकाना व वसूली करना ही है।

दूसरी तरफ हर जिले में 4से 10 11 तक खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की हुई है उनका भी यही काम है, कि बच्चे छोटे खाद्य व्यापारियों दुग्ध विक्रेताओं दुकानदारों चाय नाश्ते मिठाई नमकीन किराने की दुकानों होटल रेस्टोरेंट आदि में घुसकर उनके नमूने लेना उनके खाद्य वस्तुओं की जांच करना। प्रयोगशालाओं में भेज कर जांच करवाना अमानक पाए जाने पर उनके विरुद्ध दंड आदि की कार्यवाही करना, प्रकरण को न्यायालय में लगाना उसकी पैरवी करना और दंड के साथ सजा करवाने का कार्य करते हैं। इसकी आड़ में ये सारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी दूधियों से लेकर चाय नाश्ते पान की दुकानों से बड़े खाद्य वस्तु निर्माताओं विक्रेताओं तक से मासिक वसूली करते हैं जो प्रतिमा लगभग 25 लाख से लेकर करोड़ों तक शहर की आबादी व खाद्य प्रसंस्करण निर्माता विक्रेताओं की संख्या के अनुसार होती है। जबकि यहीखाद्य सुरक्षा अधिकारी सन 1984 से अभी तक सांची व अमूल दूध जो अपने टीवी पर समाचार पत्रों के विज्ञापनों में वे दूध, आइसक्रीम, घी मक्खन, मिठाई, मीठे दूध छाछ दही आदि के पैकेट में गाय का शुद्ध ताजा दूध व उससे निर्मित लिखते हैं। और उसमें जो बटर ऑयल, फेट आदि की मात्रा पैकेट पर लिखते हैं वह बिल्कुल नहीं पाई जाती। फिर भी अमूल अकेले मध्य प्रदेश में प्रतिदिन 10 लाख लीटर से ज्यादा दूध वह उसके उत्पाद पूरे मध्य प्रदेश के शहरों में बेंचता है। वही हाल साक्षी का भी है आखिर यह सरकारी सहकारिता में चलने वाली संस्थाओं के उत्पादन का नमूने क्यों नहीं लिया जा रहे जब एक बार मैंने सन 2006 में इस प्रश्न को विधानसभा में उठा दिया था तब स्वीकार किया कि हां 1984 से हमने सांची के उत्पादों के नमूने नहीं ली है वही हाल अमूल का भी है जब इसके संबंध मेंखाद्य सुरक्षा अधिकारियों से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि उनके दूध के नमूने लेने पर सांची के मामले में सीधा कलेक्टर और अमूल के मामले में नमूने लेने पर सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय सेफोन आता है जिस पर कलेक्टर हम को नौकरी से हटाने निलंबित करने की धमकी देकर उनके नमूने लेने से रोक देता है। इसके दूसरी ओर खाद्य सुरक्षा के अधिकारियों की मीटिंग वसूली के लिए चमकने धमकाने के लिए संभागीय आयुक्त भी लेने लगा है। जबकि जबकि उनकी मीटिंग सलाह और मॉनिटरिंग करने का काम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का है और उससे ऊपर संभागीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मीटिंग मॉनिटरिंग आदि का कार्य कर सकता है। यह वसूली के लिए चमकने धमकाने का कार्य इंदौर में संभागीय आयुक्त जो पूर्व से ही घोर भ्रष्ट दीपक सिंह ने ही नहीं किया उज्जैन में संजय अग्रवाल ने भी किया। और बार-बार छापे जाने के बाद में भी जिले का कलेक्टर और संभागीय आयुक्त यदि मीटिंग ले ही रहे हैं तो क्यों नहीं बोलते कि वह सांची और अमूल के दूध व उसके अन्य उत्पादों के नमूने भी लें। जांच करें, नमूने अनुचित मिलावटी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को दंडवा सजा करवा जबकि यह स्पष्ट है कि देश मेंऔर मध्य प्रदेश में 7 करोड़ की आबादी पर 70 लाख दुधारू गाय भी नहीं है। वही हाल गुजरात का हैतो आखिर सांची और अमूल प्रतिदिन प्रदेश में मिलकर एक करोड़ लीटर दूध की आपूर्ति कहां से कर रहे हैं जबकि 60% दूध व उसकी अन्य खाद्य सामग्री छोटे दूध विक्रेता शहर की डेरियां मिठाई आइसक्रीम निर्माता बेच रहे हैं सच तो यह है। की प्रदेश में भी मात्र 40 लाख दुधारू पशुओं से 15से 20 लाख गाय भैंस दुधारू होने के साथ मात्र 40 से 50 लाख लीटर दूध देती है। 80% दूध स्तरहीन मिलावटी और रसायनों से बना हुआ है।

आखरी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शॉपिंग मालस उनके खाद्य सामग्री के पेकेज्ड और बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियां आईटीसी युनिलीवर पार्ले अडानी अंबानी टाटा बिरला मित्तल अमेजॉन वॉलमार्ट आदि की पैकेज्ड सामग्रियों के नमूने क्यों नहीं लेते? खाद्य वस्तुओं बिस्किट टॉफी कोल्ड ड्रिंक दूध दही जूस चाय कॉफी दालें आटा शक्कर घी तेल आदित्य नमूने कितने लिए कितने फेल हुए आदि की जानकारी खुले में केंद्रीय खाद एवं औषधि नियंत्रक की अपनी राष्ट्रीय स्तर पर और राज्यों के स्तर पर अपनी वेबसाइट पर जन दर्शन और जानने के लिए क्यों नहीं डाली जाती? सूचना का अधिकार में इंदौर उज्जैन देवास धार शाजापुर रतलाम मंदसौर नीमच खंडवा खरगोन बड़वानी बुरहानपुर अलीराजपुर आगर मालवा आदि से जानकारी मांगी जाती है तो हजारों रु की फोटोकॉपी के मांग पत्र पहुंचाये जाते हैं। जब मध्य प्रदेश सरकारसन 2010 से सारा काम कंप्यूटर पर करनेको पेपरलेस वर्क करने की बात करती हैऔर सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2(र)iv में भी सीडी या साइट का पता मांगा जाता है। तो वह देने की अपेक्षा फोटो कॉपी देने प्रति पेज 15 से 20 रु की बात की जाती है। जब उनकी अपील लगाई जाती है। तो संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारीयो कोरिजेक्ट करने की अपेक्षा जितना धन मांगा जाता है वह जमा करने की बात करता है। जब उनसे कहा गया कि जब सारा काम आप कंप्यूटर पर करते हैंतो उसकी सीडी बना कर देने में क्यातकलीफ है तो बोला कहा जाता है। कि सरकार कुछ भी बोलती हैहमारे सारे नमूना, न्यायालय पंजी, खाद्य एवं औषधि के नमूने लेने सामग्री क्रय करने के बिल भुगतान आदि का सारा कार्य कागजों पर ही होता है। जबकि सच यह भी है कि यह सारा कार्यबिलों का भुगतान आदि का कार्य जो ऑनलाइन भुगतान किए जाते हैं सब कंप्यूटर पर ही होता है परंतु जानबूझकर यह खाद्य सुरक्षा अधिकारी सह निरीक्षक वह औषधि निरीक्षक अपने सारे कुकर्मों व भ्रष्टाचार छुपाने के लिए जानबूझकर जानकारी नहीं देते हैं बेशक सारे खाद एवं सुरक्षा अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी से लेकर अपने मुख्यालय के आयुक्त प्रधान सचिव और मंत्री को भी सालों एक ही जगह पर जमे रहने और मोटी वसूली करने के कारण लाखों में चुकाते हैं। जहां तक औषधि निरीक्षकों का सवाल है। 90% नए औषधि निरीक्षकों को मासिक वसूली के अतिरिक्त ना तो नमूना लेना आता है। यदिकिसी तरह उत्पादक और विक्रेता के यहां जाकर नमूने लेकर भेज भी दिए तो ना न्यायालय प्रकरण बनाना प्रस्तुत करने का कार्य भी नहीं आता और इसीलिए प्रदेश में अधिकांश स्तरहीन औषधियां, दवा के पैकेट या रैपर परजो स्तर व सामग्री लिखी होती है। उसकी मात्रा में हुआ उतने स्तर की नहीं होती। फिर फिर इंदौर में हर सोम व मंगलवार को भोपाल की 3 से 5 औषधि निरीक्षकों की टीम आती है। साथ ही इंदौर में बैठे पांच औषधि निरीक्षकों के साथ मिलकर पूरे इंदौर-उज्जैन संभाग के 15 जिलों के औषधि निर्माताओं से जो 80 लाख से एक करोड़ तक दवा निर्माताओं से अगले बैच की अनुमति व नमूने लेने, नई औषधि इंजेक्शन आदि बनाने की आज्ञा व खानापूर्ति की कीमत लाखों में वसूल कर चली जाती है। यही कारण है कि ये भ्रष्ट जानकारी देने में नाटक नौटंकी करते हैंऔर यहां बैठा मुख्य चिकित्सा अधिकारी घोर भ्रष्ट और डफर अपील की सुनवाई करने और विधि अनुसार निर्णय देने से बचता है।

सूचना का अधिकार को लगे 19 साल गुजर गए परंतु हरामखोरों ने केंद्र से लेकर राज्यों तक के खाद्य एवं औषधि प्रशासक एवं नियंत्रक ने अपनी विभागीय इंटरनेट साइट पर आज तक कौन सा अधिकारी व निरीक्षक किस जिले में कहां पदस्थ है उसके क्या-क्या कार्य हैं किसने कितने नमूने लिए कितने फेल हुए कितनों के न्यायालयीन प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए गए कितनो में सजा व दंड किस कारण से किस उत्पाद के लिए हुआ। नहीं बताया जाता। बेशक यह साइट पूर्णताः सार्वजनिक दर्शन के लिए नहीं है पर यह सारा कार्य विभागीय लोगों के लिए पूर्णता कंप्यूटराइज है। दूसरी तरफ सरकार पत्रकारों व अपने विरोधियों के टेलीफोन टेप करती है कभी खाद्य एवं औषधि विभाग के सभी निरीक्षकों और अधिकारियों के मोबाइल टैप करके भी पता लगाये की कौन प्रतिदिन और हर माह कितनी कमाई कर रहा है? किसके पास कितनी संपत्ति है? कौन-कौन से षड्यंत्र रचकर मिलावटी कंपनियों व निर्माताओं को कितना मोटा लेनदेन करके बचा रहा है? तो मालूम पड़ेगा यथार्थ में यह विभाग जिसके निरीक्षकों के पास 10-12 साल में ही करोड़ों रुपए की संपत्ति कैसे एकत्रित हो जाती है? मालूम पड़ेगा।

साप्ताहिक समय माया

बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करने के 10 सुझाव

जब आप बच्चे थे, तो क्या आप अपने भाई-बहनों के साथ सोफे पर बैठकर इस बात पर झगड़ते थे कि आप परिवार के टीवी पर कौन सा शो देखेंगे आज, जब स्क्रीन को नियंत्रित करने की बात आती है, तो आपके बच्चों के पास निश्चित रूप से कम सीमाएँ होती हैं। वे एक साथ कई शो देख सकते हैं, और उन्हें जहाँ भी जाते हैं, अपने साथ ले जा सकते हैं। तकनीक जितनी अद्भुत है, आपका बच्चा इससे कम समय में भी लाभ उठा सकता है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अनुसार, होमवर्क के अलावा, स्कूल जाने वाले बच्चों को हर दिन स्क्रीन के सामने एक या दो घंटे से ज़्यादा नहीं बिताना चाहिए।

आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान के प्रतिष्ठित प्रोफेसर, पीएचडी क्रेग एंडरसन कहते हैं, 'नवजात शिशुओं से लेकर किशोरावस्था और यहां तक कि युवा वयस्कों तक, बच्चों पर स्क्रीन टाइम के कई संभावित हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं।'

एंडरसन का कहना है कि जब बच्चे बहुत सारे तेज गति वाले कार्यक्रम देखते हैं, जिनमें एक दृश्य से दूसरे दृश्य में तेजी से बदलाव होता है, तो बाद में उन्हें कक्षा में ध्यान केंद्रित करने में परेशानी हो सकती है।

अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स काउंसिल ऑन कम्युनिकेशंस एंड मीडिया के अध्यक्ष डेविड हिल, एम.डी. का कहना है कि जो बच्चे स्क्रीन के सामने बहुत अधिक समय बिताते हैं, उन्हें अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे बहुत कम नींद आना या बहुत अधिक वजन बढ़ना।

इसके अलावा, वे कहते हैं कि जो बच्चे हर दिन घंटों टीवी देखते हैं और वीडियो गेम खेलते हैं, वे सीखने के लिए आमने-सामने के अवसरों, बाहर खेलने के समय और दोस्तों के साथ जुड़ने से चूक सकते हैं। वे कहते हैं, 'हमारा सबसे बड़ा सवाल यह होना चाहिए कि 'यह स्क्रीन टाइम किस चीज़ को विस्थापित कर रहा है?''

हर जगह स्क्रीन होने के कारण, बच्चों के साथ बिताए जाने वाले समय को कम करना और भी मुश्किल लग सकता है। लेकिन सीमाएं तय करना उचित है। उन्हें उन डिवाइस से दूर रखने के लिए ये सुझाव आज़माएँ - कम से कम, कुछ समय के लिए।

1. अपने बच्चों को उनका खुद का टैबलेट या स्मार्टफोन न दें। हार्वर्ड टीएच चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में स्वास्थ्य समाजशास्त्र के प्रोफेसर, पीएचडी स्टीवन गोर्टमेकर कहते हैं, 'अपने बच्चों के साथ बातचीत करें। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देने के बजाय ऐसा करें।'

2. कंप्यूटर और टीवी को अपने घर के साझा स्थानों पर ही रखें । जब आपके बच्चे रसोई या लिविंग रूम में स्क्रीन का उपयोग करते हैं, तो उनके द्वारा देखे जाने वाले शो, उनके द्वारा खेले जाने वाले गेम और वे कौन सी वेबसाइट देखते हैं, इस पर नज़र रखना आसान होता है।

3. अपने परिवार के शेड्यूल में तकनीक-मुक्त समय जोड़ें । हिल कहते हैं, 'किसी भी उम्र में, बच्चों को पता होना चाहिए कि स्क्रीन बंद रखने के लिए कुछ खास समय होते हैं, जैसे भोजन के समय और सोने से पहले।' इससे भी बेहतर, हर हफ़्ते समय निकालें जब परिवार साथ मिलकर कुछ मज़ेदार करे - डिवाइस की अनुमति नहीं।

4. ध्यान रखें कि आप अपने डिवाइस का कितनी बार इस्तेमाल करते हैं । अगर आप अपना चेहरा अपने फोन में छिपाकर रखेंगे, तो आपके बच्चे स्क्रीन से दूर रहने का कोई अच्छा कारण नहीं समझ पाएंगे। साथ ही, ये डिवाइस आपके बच्चों के साथ बिताए जाने वाले समय को भी प्रभावित करते हैं। फास्ट-फूड रेस्तराँ में परिवारों का अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं ने पाया कि माता-पिता अक्सर टेबल पर बैठे बच्चों की तुलना में अपने स्मार्टफ़ोन पर ज्यादा ध्यान देते थे।

5. स्क्रीन के इस्तेमाल पर सीमाएं लगाना एक नियमित हिस्सा बनाइए। जब नियम स्पष्ट और सुसंगत होते हैं, तो आप बच्चों को यह बताने पर रोज़ाना होने वाली लड़ाइयों से बच सकते हैं कि टीवी, कंप्यूटर या फोन बंद करने का समय हो गया है।

6. स्क्रीन-टाइम की अलग-अलग सीमाओं के बारे में बताने के लिए तैयार रहें। जब आपके बच्चे किसी दोस्त के घर पर घंटों टीवी देखते हैं, तो उन्हें आश्चर्य हो सकता है कि आपके नियम अलग क्यों हैं। एंडरसन कहते हैं, 'ये आपके बच्चों के साथ अपने परिवार के मूल्यों के बारे में बातचीत करने के अवसर हैं।'

7. अपने बच्चों को मौज-मस्ती करने के दूसरे तरीके खोजने में मदद करें। हिल कहते हैं, 'अगर किसी बच्चे के पास स्क्रीन पर घूरने के अलावा कोई काम नहीं है, तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए जब वह ऐसा करता है।' जब आपके बच्चे कहें कि उनके पास करने के लिए और कुछ नहीं है, तो उनके पास दूसरे विकल्प जैसे कला सामग्री, किताबें, फ्रिसबी और बाइक रखें।

8. तकनीक को अपने लिए काम में लाएं। ऐसे प्रोग्राम और ऐप का इस्तेमाल करें जिन्हें आप एक निश्चित समय के बाद कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन को बंद करने के लिए सेट कर सकते हैं।

9. जैसे-जैसे आपका बच्चा बड़ा होता जाता है, स्क्रीन-टाइम सीमाएँ समायोजित करें। हिल कहते हैं, 'मिडिल-स्कूल के बच्चों और किशोरों के लिए, माता-पिता उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक शामिल करना चाह सकते हैं।' आप उनसे इस बारे में बात कर सकते हैं कि पूरे परिवार को कितना स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए। एक बार जब आप कोई योजना बना लें, तो उस पर टिके रहें।

10. अपने पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स को दान करने या रीसाइकिल करने पर विचार करें। 'आम तौर पर घरों में बहुत सारे उपकरण होते हैं, और वे बच जाते हैं और दूसरी जगहों पर ले जाए जाते हैं,' गोर्टमेकर कहते हैं। 'एक सूची बनाना और यह देखना अच्छा है कि क्या आप तकनीक को सीमित नहीं कर सकते हैं।'

WHO के इशारे पर 5 करोड़ उद्योग धंधों को चौपट 25 करोड़ को बेरोजगार करने का षड़यंत्र

कभी अमूल, सांची के दूध व अन्य उत्पादों के भी लो नमूने

खाद्य सुरक्षा अधिकारी व औषधि निरीक्षक छोटे विक्रेताओं को ही धमकाते व वसूली करते हैं। 90% औषधि निरीक्षकों को नमूने लेना और केस लगाना भी नहीं आता।

भारत में वर्तमान सरकार अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय षडयंत्र कारी संगठनों विश्व घातक संगठन WHO से मोटा हजारों करोड़ों में कमीशन खा उनके इशारे पर नाच

सन 2014 में सत्ता संभालने के बाद आते ही सफाई के नाम पर देश में लगभग 5 करोड़ से ज्यादा ठेलो व पगमार्गों पर शहरीय आबादी में अपना व्यवसाय करने वालों को साफ कर दिया गया। उसके आगे बढ़करफिर कैशलेस का तांडव किया गया ताकि अधिकांश नगद लेनदेन को हतोत्साहित करके ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था में बैंक खातों के माध्यम से सब का डाटा इकट्ठा कर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उसके विश्लेषण के माध्यम से बाजार में गरीब व्यक्तियों की आवश्यकता और आपूर्ति पर कब्जा करने का षड़यंत्र करने के अवसर प्रदान किए गए। अगली कहानी 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी की घोषणा कर लगभग 60 करोड लोगों के सभी प्रकार के व्यवसायों में 6 महीने तक नगदी का संकट पैदा कर उनका व्यवसाय को बाधित कर लगभग बेरोजगार बना घर बैठा दिया। इसका फायदा भी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी वालमार्ट और अमेजान के साथ देश के पूंजीपतियों अडानी अंबानी टाटा बिरला मित्तल के शॉपिंग मॉल्स कोई हुआ दूसरी सब जनता को इन सब षड्यंत्रकारीयों की लूट का शिकार होना पड़ा।

(शेष पेज 7 पर)

साप्ताहिक
समय माया
samaymaya.com

करोड़ों किसानों मजदूरों छोटे व्यवसायियों
उद्योगों, सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों
ठेका संविदा कर्मियों के हितों की रक्षा व देशी
विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के षड्यंत्रों के
विरुद्ध पिछले 25 वर्षों से संघर्षरत

साप्ताहिक समयमाया समाचार पत्र व
samaymaya.com की वेबसाइट पर
समाचार, शिकायतें और विज्ञापन
(प्रिंट एवं वीडियो) के लिए संपर्क करें

मप्र के समस्त जिलों में एजेंसी देना है
एवं संवाददाता नियुक्त करना है

मो. 9425125569 / 9479535569

ईमेल: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
संपादकः अजमेरा एस.पी. कुमार, मो. 9425125569, भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9425637958